



भारत पदक तालिका में पांचवें स्थान पर

पंच बरसे और तीन गोल्ड आए

उजाला, नागोया।

अंकुश पंघाल के गोल्ड के साथ ही 2018 के बाद मेंस बॉक्सिंग में भारत को एशियन गेम्स का पहला गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले 2018 में अमित पंघाल ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। अंकुश ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। उन्होंने उस टूर्नामेंट के फाइनल में शानदार वापसी करते हुए स्वर्ण पदक जीता था। 80 किलोग्राम भारवर्ग में ब्रॉन्ज मेडल उज्बेकिस्तान के अरक्रीनेवबोएब फजलीदीन और जॉर्डन के आयशिश हुसैन ने जीता। अंकुश के गोल्ड मेडल के साथ भारत मेडल टैली में पांचवें पायदान पर पहुंच गया है। अंकुश पंघाल का गोल्ड एशियन गेम्स 2026 में बॉक्सिंग



में भारत का छठा मेडल है। इनमें तीन गोल्ड मेडल शामिल हैं। अंकुश से पहले लवलीना बोरगोहेन और परवीन हुड्डा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। लवलीना ने 75 किलोग्राम भारवर्ग में, जबकि परवीन ने 65 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता

भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत ने चीन को फाइनल में 1-0 से हराया। भारत ने इस तरह 1982 के बाद पहली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का सुखा समाप्त किया। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर में बढ़त हासिल की और अंत तक इस बढ़त को बनाए रखा। भारत ने ना सिर्फ स्वर्ण पदक अपने नाम किया, बल्कि चीन को स्वर्ण का बचाव करने से रोका। भारतीय टीम ने चीन के खिलाफ पहले क्वार्टर से दबाव बनाया। बलजीत कौर को छठे मिनट में ग्रीन कार्ड मिला। लेकिन भारत ने चीन पर दबाव बनाया और भारत के लिए 200वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही लालरेमसियामी ने 10वें मिनट में मैदानी गोल दागा। इस तरह भारत ने शुरुआत में ही 1-0 की बढ़त बनाई। भारत को इसके बाद पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय टीम बढ़त दोगुना करने से चूक गई। हालांकि, पहला क्वार्टर समाप्त होने तक भारतीय टीम बढ़त बनाए रखी। चीन ने दूसरे क्वार्टर में आक्रामक खेल दिखाया और लगातार भारत पर दबाव बनाए रखा। चीन ने तब राहत की सांस ली, जब उसे पेनल्टी स्ट्रोक मिला। चीन के लिए बराबरी हासिल करने के यह शानदार मौका था, लेकिन भारतीय महिला टीम की अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया ने दमदार बचाव कर चीन को बराबरी करने से रोका।



काँकरोच जनता पार्टी का जेल भरो आंदोलन मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

मुंबई। काँकरोच जनता पार्टी आज मुंबई के शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन कर रही है। वे चुनाव आयोग में असहमति के कथित विवाद और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि अगर कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो यह आंदोलन मुंबई से शुरू होगा और बाद में भारत के दूसरे शहरों में भी फैल जाएगा। दिपके ने सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा करते हुए समर्थकों से गांधी जयंती पर लोकतंत्र बचाने का आह्वान किया। शिवाजी पार्क में प्रस्तावित सभा से पहले दादर स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ताजा अपडेट के लिए इंडिया टुडे इन को फॉलो करें।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, सीजेपी नेता अभिजीत दिपके ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लोक मामले



फर्जी नैरेटिव बेनकाब : फडणवीस

मुंबई में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर काँकरोच जनता पार्टी और कुछ नागरिक संगठनों ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ चलाया जा रहा फर्जी नैरेटिव चुनाव आयुक्तों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बेनकाब हो गया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन के बीच पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा, पूरा मामला सामने आ चुका है। तीनों चुनाव आयुक्तों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका फर्जी नैरेटिव बेनकाब हो गया है। इसके बावजूद अब भी इस फर्जी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वे इसमें सफल नहीं होंगे।

को लेकर जंतर-मंतर पर हुए विरोध उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र प्रदर्शन के दो महीने के भीतर ही एक फडणवीस को प्रदर्शनकारियों को और आंदोलन की ज़रूरत पड़ गई। गिरफ्तार करने की चुनौती भी दी।

कांग्रेस को 55 सीटें देने का रखा प्रस्ताव

यूपी चुनाव 2027 खुद 350 सीटों पर लड़ेगी सपा

लखनऊ। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक पार्टियां अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिशें बढ़ा रही हैं। हालांकि इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन गठबंधन के सहयोगी दल ज्यादा सीटें पाने के लिए दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है और इसके बजाय पार्टियों के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें बहुत कम सीटें देने पर विचार कर रही है।

समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ सीट-शेयरिंग का फॉर्मूला तय करते



समय चुनावी प्रदर्शन पर ध्यान दे रही है। स्कूजगठबंधन के तहत कांग्रेस को लगभग 53 से 55 सीटें देने का प्रस्ताव दे रही है, जबकि पार्टी खुद लगभग 350 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। खबरों के अनुसार, समाजवादी पार्टी का यह रुख इस बात के आकलन पर आधारित है कि किस सीटों पर उसकी स्थिति सबसे मजबूत है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां उसकी चुनावी मौजूदगी मजबूत है। प्रस्तावित फॉर्मूले में 2024 के

लोकसभा चुनावों के नतीजों को भी ध्यान में रखा गया है। कांग्रेस ने 2024 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में छह लोकसभा सीटें जीती थीं। इन सीटों के अंतर्गत 30 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जबकि 11 विधानसभा सीटें उन लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं जहां कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गई थी। सूत्रों के अनुसार, स्कू कांग्रेस के लिए 53 से 55 सीटों का प्रस्तावित आंकड़ा तय करने के लिए इन क्षेत्रों में कांग्रेस के विधानसभा-वार प्रदर्शन को अपने हिसाब-किताब का आधार बना रही है। इसी तरह, समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन का भी आकलन कर रही है, जिसमें जीती गई 37 सीटें और वे क्षेत्र शामिल हैं जहां वह हार गई थी लेकिन विधानसभा स्तर पर उसे बढ़त मिली थी।

बिहार विधान परिषद उपचुनाव कांग्रेस ने 5 सीटों पर उतारे प्रत्याशी

पटना। दो अक्टूबर बिहार में आगामी विधान परिषद चुनाव में पांच सीट पर चुनाव लड़ने के कांग्रेस के फैसले के बाद विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन में दरार की अटकलों को पार्टी ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। इन पांच में से अधिकतर सीट पर कांग्रेस का मुकाबला उसकी सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवारों से होगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी (बीपीसीसी) के अध्यक्ष राजेश कुमार राम ने कहा कि पार्टी का फैसला कार्यकर्ताओं की भावनाओं और जनता की इस धारणा के अनुरूप है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सामने प्रमुख चुनौती के रूप में उभर रही है। उन्होंने कहा, "हम जिन सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां हमारा मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से होगा। बाकी सीट पर हम अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे।" उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने विधान परिषद की कुल आठ सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बृहस्पतिवार देर रात पांच उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी निर्वाचन क्षेत्रों में राजद भी मैदान में है।

करोड़ों के कोल लेवी मामले में देवेंद्र यादव को ईओडब्ल्यू का नोटिस

रायपुर। करीब 540 करोड़ रुपये के कोल लेवी मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने नोटिस जारी कर 5 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे रायपुर की विशेष अदालत में पेश होने का नोटिस दिया है। जांच एजेंसी इस मामले में अपनी जांच पूरी कर आरोप पत्र पेश करेगी।

सितंबर के आखिरी सप्ताह में भी देवेंद्र यादव से रायपुर स्थित आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के दफ्तर में दो घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी। पूछताछ का मुख्य आधार सूर्यकांत तिवारी से जुड़ी जांच में मिली डायरी में देवेंद्र यादव का नाम और पैसों के लेन-देन से जुड़ी जानकारी बताई गई है। हालांकि, देवेंद्र यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है।

8 पूर्व नक्सलियों ने ओपन स्कूल से 10वीं परीक्षा पास की

जगदलपुर। बस्तर में आत्मसमर्पण के बाद पूर्व नक्सलियों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिशों के बीच 8 पूर्व नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की है। इनमें बस्तर के 6, कांकेर और बीजापुर के 1-1 पूर्व नक्सली शामिल हैं। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के स्टेट कमेटी सदस्य रहे भास्कर और महाराष्ट्र के गढ़चिरोली की गीता नारोटे ने प्रथम श्रेणी हासिल की है। आत्मसमर्पण के बाद इन पूर्व नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिक्षा के साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से भी जोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली की रहने वाली गीता नारोटे ने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण छठवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद वह नक्सली संगठन में शामिल हो गईं। करीब दो दशक तक संगठन में रहने के दौरान वह घायल नक्सलियों के उपचार का काम करती रहीं। टांके लगाने, इंजेक्शन लगाने और दवाइयों की जानकारी होने के कारण संगठन में उन्हें नक्सली डॉक्टर गीता

आराधना मिश्रा मोना को सौंपी उत्तर प्रदेश इकाई की कमान

लखनऊ। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में एक बड़ा और रणनीतिक फेरबदल किया है। कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, पार्टी हाईकमान ने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उनके पद से मुक्त करते हुए उनके योगदान की सराहना की है, और उनकी जगह प्रतापगढ़ की विधायक व वरिष्ठ नेत्री आराधना मिश्रा मोना को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (यूपीसीसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस के इस कदम को बेहद सोची-समझी राजनीतिक रणनीति माना जा रहा है। पार्टी इसके जरिए एक साथ महिला और ब्राह्मण मतदाताओं (सोशल इंजीनियरिंग) को साधने की पुर्नजो कोशिश कर रही है। आराधना मिश्रा कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की पुत्री हैं और विधानसभा में पार्टी की एक बेहद मुखर और मजबूत आवाज मानी जाती रही हैं।

3 देशों को आकाश मिसाइल सिस्टम का सफल निर्यात

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि भारत के अपने बनाएआकाश एयर डिफेंस सिस्टम को तीन देशों - आर्मेनिया, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान - को सफलतापूर्वक एक्सपोर्ट किया गया है। इससे भारत में बने मिलिट्री इक्विपमेंट को दुनिया भर में बढ़ती मांग का पता चलता है। सिंह ने एएनआई के साथ एक खास बातचीत में कहा पहला ग्राहक आर्मेनिया था, जिसने कई बैटरी ली हैं। इसके बाद, हमने इसे ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भी एक्सपोर्ट किया है। प्रोडक्शन अब स्थिर हो गया है। हमारे पास अपनी सेनाओं के लिए भी और ऑर्डर हैं, और मुझे यकीन है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से और भी कई ऑर्डर मिलेंगे। सिंह ने आकाश को भारत के डिफेंस सेक्टर की सफलता की कहानियों में से एक बताया और कहा कि यह सिस्टम देश की अपनी मिसाइल डिज़ाइन और मैनुफैक्चरिंग क्षमताओं के परिपक्व होने को दिखाता है।



चशमदीन ने बताई कैप्टन स्मिट की जान बचाने की दास्तां

40 मिनट का खौफनाक हवाई सफर, काँकपिट में खून-खराबा

नई दिल्ली। दुबई से इस्त्राइल जा रही उड़ान में सवार 174 यात्रियों के लिए एक सफर किसी बुरे सपने जैसा था। सह-पायलट द्वारा भारतीय कैप्टन स्मिट मच्छर पर किए गए जानलेवा हमले और चाकूबाजी के बाद विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। इससे केबिन में अफरा-तफरी मच गई। लहलुहान होने के बावजूद भारतीय कैप्टन ने हिम्मत नहीं हारी। तुरंत काँकपिट का दरवाजा खोलकर यात्रियों तक संदेश पहुंचाया। इस खौफनाक मंजर के दौरान विमान में मौजूद एक यात्री (अलमोग) ने अमर उजाला से खास बातचीत की। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम, भारतीय कैप्टन की अदम्य बहादुरी और

काँकपिट के भीतर मचे घमासान का आंखों देखा हाल बताया। **सवाल :** इस खौफनाक हादसे के बाद अब आप और आपका परिवार कैसा महसूस कर रहे हैं ? **अलमोग :** हम ठीक हैं और धीरे-धीरे इस सदमे से उबर रहे हैं। हमने जिस खौफनाक मंजर का सामना किया है, उसे पूरी तरह समझ पाने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन हम स्थिति को संभाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हीरो, ग्लोबल हीरो कैप्टन स्मिट को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते देखना हमारे लिए बेहद भावुक और सुखद पल था। **सवाल :** उस पलाइट में असल में

हुआ क्या था ? शुरुआत से लेकर लैंडिंग तक क्या-क्या घटा ? **अलमोग :** यह दुबई से तेल अवीव की एक सामान्य फ्लाइट थी। शुरुआत के दो घंटे सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। लेकिन अचानक विमान बहुत तेजी से गोता खाने लगा। करीब 30 सेकंड तक विमान तेजी से नीचे गिरा, फिर थोड़ा संभला और दोबारा रोलर कोस्टर की तरह नीचे जाने लगा। जी-फोर्स इतना ज्यादा था कि संभलना मुश्किल हो रहा था। लगभग 50 सेकंड बाद जब विमान थोड़ा स्थिर हुआ, तो हमने देखा कि कुछ लोग काँकपिट की तरफ दौड़े। करीब 4-5 मिनट बाद उनमें से एक व्यक्ति ने आकर बताया कि काँकपिट में



एक पायलट ने दूसरे पायलट को चाकू मार दिया है। इसके बाद एक यात्री और क्रू मेंबर ने मोर्चा संभाला। संयोग से फ्लाइट में बाहर एक तीसरा पायलट भी सफर कर रहा था, जिसने काँकपिट में जाकर विमान का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और सुरक्षित लैंडिंग की जगह

तलाशने लगा।

सवाल : जब विमान अचानक नीचे गिर रहा था, तो केबिन का माहौल कैसा था ? **अलमोग :** कोई चेतावनी या अलर्ट नहीं मिला था। पहले हमें लगा कि यह सामान्य टर्बुलेंस (हवा का दबाव) है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक खतरनाक था। विमान का नीचे गिरने का कोण बेहद डरावना था। मैंने अपने जीवन में सैकड़ों-हजारों बार उड़ान भरी है, लेकिन ऐसा भयानक अनुभव कभी नहीं देखा। हमारे पास सीटबेल्ट तक बांधने का समय नहीं था। मैंने तुरंत अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को सीटबेल्ट बांधी। हम पंक्ति 19 और 20

पर विंग (पंखों) के ठीक ऊपर बैठे थे और देख पा रहे थे कि विमान के पंख संतुलन बनाने के लिए किस कदर जूझ रहे थे। **सवाल :** काँकपिट का दरवाजा कैसे खुला और हमलावर को कैसे पकड़ा गया ? **अलमोग :** काँकपिट के अंदर क्या चल रहा था, वह हम सीधे नहीं देख पा रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि अंदर जबरदस्त संघर्ष हुआ था। कई बार चाकू लगने के बावजूद हमारे हीरो कैप्टन स्मिट ने अंदर से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही पहली पंक्ति में बैठे 3-4 यात्री काफी तेजी से अंदर घुसे, समाझिए बिल्कुल बिजली की

रफ्तार से। उन्होंने हमलावर सह-पायलट को तुरंत नीचे पटक दिया, उसके हाथ-पैर बांधे और विमान की कंट्रोल स्टिक को स्थिर करने में मदद की। जब तक विमान सकुटी अरब में सुरक्षित लैंड नहीं हो गया, तब तक दो लोग लगातार हमलावर पर नजर रखे हुए थे। **सवाल :** कैप्टन स्मिट मच्छर की हालत उस वक्त कैसी थी ? **अलमोग :** कैप्टन बहुत बुरी तरह घायल थे। उन पर चाकू से कई बार किए गए थे और वे चिंतगी और मौत के बीच झूल रहे थे। वे होश में नहीं थे। हमारी किस्मत अच्छी थी कि विमान में एक डॉक्टर मौजूद थे।

दो करोड़ के गांजा के साथ दो आरोपी गिरफ्तार



जशपुर। नशे के खिलाफ जशपुर पुलिस के ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लावाकेरा पुलिस चेकिंग बैरियर पर पुलिस ने मिर्ची की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा 440.63 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मामले में उत्तरप्रदेश के प्रयागराज निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 20 लाख 31 हजार 500 रुपये है। पुलिस के मुताबिक, 2 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 9 बजे एंटी नारकोटिक्स और थाना तपकरा पुलिस की संयुक्त टीम लावाकेरा चेकिंग बैरियर पर संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान ओडिशा की ओर से आ रहे टाटा ऑटोस पर मिनी ट्रक क्रमांक यूपी –71–टी-6592 को संदेह के आधार पर रोका गया। वाहन में सवार दो व्यक्तियों ने अपना नाम मो. वसीम (28) और मो. आसिफ (34) बताया। दोनों प्रयागराज, उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने ट्रक में मिर्ची की बोरियां लोड होने और उन्हें ओडिशा से उत्तर प्रदेश ले जाने की बात कही। संदेह होने पर पुलिस ने वाहन में लदे सामान की बारीकी से जांच की। ऊपर की ओर मिर्ची की बोरियां मिलीं, जिन्हें हटाने पर नीचे रखी बोरियों में टेप से लिपटे पैकेट दिखाई दिए। पैकेट खोलकर जांच करने पर उनमें गांजा मिला। पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में जांच की तो 14 बोरियों में कुल 440 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन 440.63 किलोग्राम निकला। पुलिस ने गांजे के संबंध में आरोपियों से वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद गांजा और तस्करी में इस्तेमाल मिनी ट्रक को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, जब्त गांजे की कीमत 2 करोड़ 20 लाख 31 हजार 500 रुपये और वाहन की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये है। इस तरह मामले में कुल 2 करोड़ 40 लाख 31 हजार 500 रुपये की जब्त की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि गांजा ओडिशा के बोध क्षेत्र से लेकर प्रयागराज ले जाया जा रहा था। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा किससे खरीदा गया था और उत्तरप्रदेश में इसे किस व्यक्ति तक पहुंचाया जाना था। पुलिस ने मामले में एंड-टू-एंड विवेचना शुरू कर दी है। तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांची जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना तपकरा में धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, मामले में संसिल पाए जाने वाले अन्य लोगों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।जशपुर पुलिस के अनुसार, जनवरी 2026 से अब तक गांजा तस्करी के 16 मामलों में करीब 8 करोड़ रुपये कीमत का 1906 किलो गांजा बरामद किया जा चुका है। इन मामलों में 22 तस्करी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल 17 कार और एक पिकअप वाहन भी जब्त किए गए हैं। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेश सिंह के नेतृत्व में चलाता जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पत्नी घर नहीं लौटी, दामाद ने ससुराल में लगाई आग

सूरजपुर। रामानुजनगर क्षेत्र में घरेलू विवाद के बाद दामाद ने अपने ससुराल के घर में घुसकर आग लगा दी। इस दौरान घर में बुजुर्ग और 6 साल का बच्चा सो रहे थे, जो झुलूस गए। सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया रामानुजनगर थाना क्षेत्र के खालापार निवासी भजन सिंह का अपनी पत्नी संगीता के साथ विवाद हुआ। चार पांच दिन बाद भी जब पत्नी घर नहीं लौटी तो भजन सिंह अपने ससुराल रामेश्वरम गांव पहुंचा। पत्नी के मायके में नहीं होने पर इसका जिम्मेदार अपने साले कल सिंह को ठहराते हुए उसके साथ विवाद किया और ससुराल वालों को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। देर रात भजन सिंह वापस ससुराल आया और घर के अंदर घुसा और एक ही बिस्तर पर कंबल ओढ़े सो रहे छ-वर्षीय पुते सत्यम सिंह और उसके दादा जय सिंह के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। घटना के बाद परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से 6 वर्षीय सत्यम और उसके दादा जयसिंह लगभग 20 प्रतिशत झुलस गए। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए।

चेकिंग के नाम पर बुजुर्ग से लूटी अंगूठियां, महीने में तीसरी वारदात

कोरबा। जिले में दिनदहाड़े ठगी और चैन स्नेचिंग की दो घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दर्री थाना क्षेत्र में बाइक सवार ठगों ने पुलिस चेकिंग का डर दिखाकर 65 वर्षीय बुजुर्ग से दो सोने की अंगूठियां ठग लीं। वहीं सिविल लाइन रामपुर क्षेत्र में मॉनिंग वॉक पर निकली महिला से बाइक सवार बदमाशों ने चैन स्नेचिंग की कोशिश की। पहली घटना दर्री थाना क्षेत्र के प्रगति नगर रोड की है। यहां 65 वर्षीय भागीराम कर्म प्रगति नगर रोड स्थित षट्रुस्स क्वार्टर ऑफिस के सामने से गुजर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने बुजुर्ग से कहा कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है और सोना-चांदी उतारकर रख दें। उनकी बातों में आकर भागीराम ने अपनी दो सोने की अंगूठियां उतार दीं। आरोपियों ने अंगूठियां अपने कब्जे में लीं और बाइक से फरार हो गए। ठगी गई दोनों अंगूठियों की कीमत करीब 80 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 304(2), 3(5) में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिवरीनारायण-खैरताल मार्ग के लिए 22 करोड़ रुपये स्वीकृत

जांजगीर-चाम्पा। जांजगीर- चाम्पा जिले के शिवरीनारायण- खैरताल मार्ग के मजबूतीकरण कार्य की बड़ी सीमागत दिया है छ शिवरीनारायण से खैरताल मार्ग के मजबूतीकरण एवं पुल-पुलिया सहित निर्माण कार्य के लिए 2208.59 लाख (22 करोड़ 8 लाख 59 हजार रुपये) की शासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही सड़क निर्माण की मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण सड़क कार्य को स्वीकृति मिली है। इससे क्षेत्र में सड़क अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अंचलों में आवागमन की सुविधाएं बेहतर होंगी। यह मार्ग लगभग 11.70 किलोमीटर लंबा है। मार्ग के मजबूतीकरण एवं पुल-पुलिया सहित निर्माण कार्य से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। जिले के प्रभारी मंत्री एवं वित्त मंत्री चौधरी के मार्गदर्शन एवं प्रयासों से भी क्षेत्र में सड़क एवं अधोसंरचना विकास के कार्यों को गति मिली है।

नशीली दवाइयों और मादक पदार्थों को किया गया नष्ट

रायगढ़। जिले में विभिन्न एनडीपीसी प्रकरणों में जप्त मादक पदार्थों एवं नशीली दवाइयों के नष्टीकरण की विधिवत कार्रवाई की गई। जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल समिति के अध्यक्ष शशि मोहन सिंह,उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के नेतृत्व में यह कार्रवाई संपन्न हुई। जिला रायगढ़ के 16 प्रकरणों में जप्त 415.991 किलोग्राम गांजा एवं 03 नाग गांजा पौधों को एसएसपी स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, जामगांव प्लांट की भट्टी में विधिवत जलाकर नष्ट किया। इसी प्रकार विभिन्न एनडीपीएस प्रकरणों में जप्त 108 नाग प्रतिबंधित सिरप तथा 529 नाग प्रतिबंधित टेबलेट/कैप्सूल, कुल 637 नाग नशीली दवाइयों को प्लांट परिसर के पास बुलडोजर/रोड रोलर से कुचलकर गट्टे में दबाकर विधिवत नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। यह किए गए मादक पदार्थ एवं नशीली दवाइयों की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 8 लाख 26 हजार 399 रुपये है। संपूर्ण कार्रवाई जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल समिति के अध्यक्ष शशि मोहन सिंह, सदस्य अनिल सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़,उत्तम प्रताप सिंह,उप पुलिस अधीक्षक रायगढ़,अभिषेक तिवारी, जिला आबकारी अधिकारी एवं पंचों की उपस्थिति में नियमानुसार संपन्न हुई।

ग्रापं सिरली में धूमधाम से मनाई महात्मा गांधी जयंती

सक्ती। सक्ती जिला कांग्रेस कमेटी एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जैजैपुर के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व लालबहादुर शास्त्री की जयंती जैजैपुर ब्लॉक के सिरली में अत्यंत धूमधाम, उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेस जनों एवं सर्वोदय के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई भव्य प्रभातफेरी से हुआ। प्रभातफेरी के दौरान कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जय जगत तथा रघुपति राघव राजा राम जैसे सुमधुर भजनों का श्रद्धापूर्वक गायन करते हुए पूरे गांव का भ्रमण किया, जिससे संपूर्ण वातावरण देशभक्ति और सर्वोदय के संदेशों से गुंजायमान हो उठा। प्रभातफेरी के पश्चात मुख्य सभास्थल पर दोनों महान विभूतियों के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने महात्मा गांधी और लालबहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके सत्य, अहिंसा, सादगी और कर्तव्यनिष्ठा के सिद्धांतों को याद किया।

नक्सलवाद छोड़ थामी किताब, 8 पूर्व नक्सलियों ने पास की 10वीं की परीक्षा

जगदलपुर। बस्तर में नक्सल हिंसा से बाहर निकलकर सामान्य जिंदगी की ओर लौट रहे पूर्व नक्सलियों की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। इसकी एक तस्वीर तब सामने आई, जब आत्मसमर्पण कर चुके 8 पूर्व नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की। खास बात ये है कि परीक्षा देने वाला एक भी परीक्षार्थी फेल नहीं हुआ। इनमें ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने बचपन में स्कूल छोड़ दिया था और बाद में नक्सली संगठन का हिस्सा बन गए, लेकिन आत्मसमर्पण के बाद जब उन्हें दोबारा पढ़ने का मौका मिला, तो उन्होंने उम्र और बीते हुए समय की परवाह किए बिना किताब उठाई और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली की रहने वाली गीता नरोटे ने छटवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। साल 2004 में वह नक्सली संगठन से जुड़ी और करीब दो दशक तक संगठन में रही। संगठन में रहते हुए घायल नक्सलियों के इलाज का काम करने के कारण उन्हें डॉक्टर गीता के नाम से भी जाना गया। 25 अक्टूबर 2025 को आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की और 35 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास कर ली। गीता को कुल 347 अंक मिले



हैं। अब उनका सपना आगे पढ़ाई कर नर्सिंग की ओर बढ़ने और समाज की सेवा करने का है। दूसरी कहानी संतोष आंचल की है। साल 2008 में संगठन में शामिल हुए संतोष ने 2025 में आत्मसमर्पण किया। घर की परिस्थितियों के कारण वह शुरुआती कक्षाओं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाया था, लेकिन संगठन में रहते हुए उसे पढ़ने का मौका मिला। आत्मसमर्पण के बाद उसने फिर से किताबें उठाईं, 10वीं की परीक्षा दी और 308 अंक हासिल किए। अब वह 12वीं की पढ़ाई करना चाहता है और आगे खेती-बाड़ी या अपना कारोबार शुरू करने की सोच रहा है।वहीं वीरू यानी रामधर कश्यप की पढ़ाई का सफर भी कई पड़ावों से होकर गुजरा। साल 2009 में संगठन में शामिल होने वाले वीरू ने जेल में

रहते हुए चौथी कक्षा की परीक्षा दी थी। मार्च 2024 में वापस लौटने के बाद अधिकारियों की पहल पर उसने ओपन स्कूल की 10वीं परीक्षा की तैयारी की। सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई की और 256 अंक हासिल कर सेकंड डिविजन से पास हुआ। अब वह आगे पढ़ाई के साथ खेती-किसानी और अपना काम करने की इच्छा रखता है। दरअसल, आत्मसमर्पण के बाद इन पूर्व नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सिर्फ सुरक्षा और पुनर्वास तक सीमित प्रयास नहीं किए जा रहे, बल्कि उनकी रुचि के मुताबिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के रास्ते भी खोले जा रहे हैं। बस्तर संभाग में 8 पूर्व नक्सलियों को ओपन स्कूल से 10वीं की परीक्षा दिलाई गई और सभी सफल रहे। इनमें बस्तर के 6, कांकर और बीजापुर के एक-एक परीक्षार्थी शामिल हैं। अब इनकी आगे की पढ़ाई को लेकर भी मदद की बात कही जा रही है। यानी लंबे समय तक संगठन और जंगल के बीच गुजरा जीवन अब धीरे-धीरे पढ़ाई, रोजगार और अपने भविष्य की योजनाओं की तरफ बढ़ रहा है। इन आठ लोगों की सफलता इस बदलाव की एक ऐसी तस्वीर है, जिसमें बीते हुए जीवन के बजाय आगे की जिंदगी को लेकर तैयारी दिखाई दे रही है।

छत्तीसगढ़

सरोदा बांध में रिकॉर्ड जलभराव, पांच प्रमुख जलाशय लबालब, किसानों के लिए अच्छी खबर

कबीरधाम। कबीरधाम जिले में पिछले दो दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने जहां कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित किया है, वहीं यही बारिश जिले के जलाशयों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। लगातार बारिश के बाद जिले के पांचों प्रमुख बांधों में जलभराव की स्थिति तेजी से सुधरी है। जल संसाधन विभाग के अनुसार अधिकांश जलाशयों में करीब 100 प्रतिशत तक पानी पहुंच चुका है। इनमें सरोदा बांध में सबसे महत्वपूर्ण जलभराव दर्ज किया गया है। बारिश से पहले



सरोदा बांध में करीब 71 प्रतिशत पानी था, लेकिन पिछले दो दिनों की तेज बारिश के बाद बांध लगभग लबालब हो गया है।

जलभराव निर्धारित क्षमता के पार पहुंचने की स्थिति में है। विभाग के अनुसार हालिया जलभराव पिछले कई वर्षों की तुलना में

उल्लेखनीय माना जा रहा है। बांधों में पर्याप्त पानी पहुंचने से जल संसाधन विभाग ने भी राहत की सांस ली है। जलाशयों में पानी की उपलब्धता बढ़ने से आगामी रबी सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही गर्मी के दिनों में जलाशयों में पानी की उपलब्धता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। कवर्धा शहर के लिए भी सरोदा बांध का भरना बड़ी राहत है।नगर पालिका के माध्यम से शहर में घर-घर पहुंचने वाले नल कनेक्शनों के जरिए

सरोदा बांध के पानी का उपयोग पेयजल और निस्तार के लिए किया जाता है। ऐसे में बांध में पर्याप्त जलभराव शहर की आगामी पेयजल जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।बारिश ने जिले के कई क्षेत्रों में परेशानी और नुकसान की स्थिति पैदा की है, लेकिन दूसरी ओर जलाशयों को भरकर किसानों और शहर के लिए पानी की चिंता को काफी हद तक कम किया है।यानी बारिश ने एक तरफ आफत दी, तो दूसरी तरफ आने वाले महीनों के लिए पानी के रूप में बड़ी राहत भी दी है

सूर्यकांत तिवारी से जुड़ा भिलाई का मकान सील

दुर्ग-भिलाई। दुर्ग जिले के छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला लेवी मामले से जुड़े कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से संबंधित बताई जा रही भिलाई की एक संपत्ति पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार देर शाम आयकर विभाग की टीम ने जुनवानी स्थित सूर्या रेजिडेंसी के मकान नंबर ए-1 को सील कर संपत्ति का कब्जा अपने नियंत्रण में ले लिया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल, तहसीलदार और राजस्व अधिकारी भी मौजूद रहे। आयकर विभाग द्वारा जारी दस्तावेज के अनुसार, यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की धारा 29(2)(बी) के तहत जब्त संपत्ति का कब्जा लेने के लिए की गई। दस्तावेज में संपत्ति का पता ए-1, सूर्या रेजिडेंसी, कोहका, भिलाई, जिला दुर्ग दर्ज है। इसका खसरा नंबर 2028/38 और क्षेत्रफल 0.02 हेक्टेयर यानी करीब 200 वर्गमीटर बताया गया है। दस्तावेज में यह कार्रवाई मनीष उपाध्याय से संबंधित मामले में जब्त संपत्ति के कब्जे से जुड़ी बताई गई है। आयकर विभाग के अधिकारी की ओर से सुपेला थाना प्रभारी को पत्र भेजकर पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद पुलिस बल और तहसीलदार की मौजूदगी में मकान को सील करने की कार्रवाई की गई। आयकर विभाग रायपुर के अधिकारी रूद्र चंद्राकर के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। उनके साथ तहसीलदार टिकेश्वर साहू, स्मृति नगर चौकी प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। टीम ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत मकान का कब्जा अपने नियंत्रण में लिया।

स्थानीय जानकारी के अनुसार, इस मकान में सूर्यकांत तिवारी, पिता स्वर्गीय शशिकांत तिवारी के रहने की बात सामने आई है। कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस दिए जाने के कारण मकान में रखा सामान पहले ही खाली कर लिया गया था।

किन्नरों और पिता-पुत्र के बीच हुई मारपीट

कोरबा। कोरबा से किन्नर और पिता-पुत्र के बीच खूनी झड़प का एक मामला सामने आया है, जहां कमेंट को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया और 10 मिपट तक लात-मुंसे चलते रहे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।यह पूरा मामला दीपका थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, किन्नर समाज के लोग दीपका क्षेत्र में ढोलक बजाते हुए दुकानों में बधाई मांग रहे थे। इसी दौरान दीपका चौक स्थित संजय पान पैलेंस पर किसी बात पर कमेंट को लेकर किन्नरों और दुकान के पास मौजूद लोगों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष हाथापाई पर उतर आए। बताया जा रहा है कि इस दौरान केजे सिंह कंपनी में काम करने वाले पंकज सिंह पर किन्नरों ने चाकू और डंडे से हमला कर दिया। चाकू लगाने से



पंकज सिंह घायल हो गया। पिता के साथ मारपीट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे उसके बेटे प्रतीक सिंह के साथ थी किन्नरों ने जमकर मारपीट की। दीपका थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष ने थाने में लिखित शिकायत नहीं दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों के सफाझाश दी है। शिकायत मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन किए अर्पित



रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने शुक्रवार को लोक भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनके चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर लोकभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भी इन महान विभूतियों को पुष्पांजलि अर्पित की।

यूथ कांग्रेस में फर्जी वोटिंग का आरोप चंद्राकर ने की सीबीआई जांच की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने यूथ कांग्रेस में कथित फर्जी वोटिंग और फंडिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की है। अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि यूथ कांग्रेस में चंदे के जरिए सदस्यता दी जा रही है और चुनाव प्रक्रिया में फर्जी वोटिंग की शिकायतें सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि इस तरह की कथित गड़बड़ियां कांग्रेस पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को प्रभावित कर रही हैं। चंद्राकर ने कांग्रेस की आंतरिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के भीतर चल रहे इस तरह के कथित सिस्टम का असर जनमानस पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को रोकने और प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने यूथ कांग्रेस में कथित फर्जी वोटिंग के साथ-साथ सदस्यता और फंडिंग से जुड़े मामलों की भी सीबीआई जांच की मांग की है।

रायपुर ग्रामीण पुलिस में बड़ा फेरबदल, 3 थानों के प्रभारी बदले

रायपुर। रायपुर जिला ग्रामीण पुलिस में तबादला आदेश जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण श्वेता सिन्हा ने तीन थानों के प्रभारियों में बदलाव किया है। जारी आदेश के मुताबिक राखी, खरोरा और माना थाना के प्रभारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है। तबादला आदेश के अनुसार प्रेमप्रकाश अवधिया को राखी थाना प्रभारी से हटाकर खरोरा थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं विद्याभूषण भारद्वाज को खरोरा से स्थानांतरित कर माना थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। एसआई दीपक कुमार साहू को राखी थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं माना थाना प्रभारी रहे एसआई जितेन्द्र डहरिया को पुलिस लाइन अटैच किया गया है। सभी अधिकारियों को नवीन पदस्थाना पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

आयुष्मान भारत से विनय को मिला निशुल्क उपचार का संबल

रायपुर। शासन का मूल ध्येय नागरिकों के कल्याण और अंत्योदय की भावना के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना है। जन-सेवा के प्रति इसी समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रत्यक्ष उदाहरण दुर्ग शहर के पोतसाय पारा निवासी बालक विनय उमरे के जीवन में देखने को मिला, जिसे आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से नई आरोग्य दृष्टि और संबल प्राप्त हुआ। बालक विनय उमरे लंबे समय से कान के पर्दे में छेद की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। इस व्याधि के कारण वह न केवल शारीरिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था, बल्कि दैनिक जीवन के कार्यों को सामान्य रूप से पूरा करने में भी उसे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। चिकित्सीय परामर्श के उपरांत डॉक्टरों ने कान के पर्दे के ऑपरेशन की तत्काल आवश्यकता जताई, जिसका संभावित खर्च लगभग 36,000 रूपए बताया गया। एक मध्यमवर्गीय परिवार के लिए यह राशि आर्थिक रूप से अत्यंत चिंताजनक और मानसिक दबाव उत्पन्न करने वाली थी। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में नागरिकों के प्रति संवेदनशील शासन व्यवस्था और आयुष्मान भारत योजना एक वरदान बनकर सामने आई।

रायपुर ग्रामीण में तीन थानों के प्रभारी बदले, एक पुलिस लाइन अटैच

रायपुर। रायपुर जिला ग्रामीण पुलिस में तबादला आदेश जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण श्वेता सिन्हा ने तीन थानों राखी, खरोरा और माना के थाना प्रभारियों को बदलने के साथ माना थाना प्रभारी को पुलिस लाइन में अटैच किया है। तबादला आदेश के अनुसार प्रेमप्रकाश अवधिया को राखी थाना प्रभारी से हटाकर खरोरा थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं विद्याभूषण भारद्वाज को खरोरा से स्थानांतरित कर माना थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। एसआई दीपक कुमार साहू को राखी थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं माना थाना प्रभारी रहे एसआई जितेन्द्र डहरिया को पुलिस लाइन अटैच किया गया है। सभी अधिकारियों को नवीन पदस्थाना पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।



दीक्षारंभ कार्यक्रम के अंतर्गत महात्मा गांधी जयंती पर स्वच्छता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

रायपुर। कृषि महाविद्यालय, रायपुर में दीक्षारंभ कार्यक्रम के अंतर्गत महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा स्वच्छता, श्रमदान एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉ. आर. पी. कुजूर, शैक्षणिक प्रभारी, कृषि महाविद्यालय, रायपुर द्वारा महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के विचारों एवं उनके जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को संदेश दिया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी, छात्रा इकाई, कृषि महाविद्यालय, रायपुर, डॉ. पायल जायसवाल ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों, विभिन्न गतिविधियों एवं स्वयंसेवकों की भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करने तथा समाज सेवा एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

इसके पश्चात डॉ. आर. के. ठाकुर, खेल प्रभारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी, छात्र इकाई ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर आयोजित विभिन्न खेल गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। डॉ. एस. के. नाग, विश्वविद्यालय सांस्कृतिक प्रभारी ने महाविद्यालय



स्तर पर आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों तथा अंतर-विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं के संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम के अगले चरण में कृषि महाविद्यालय परिसर से विश्वविद्यालय की आवासीय कॉलोनी तक लगभग 250 विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। विद्यार्थियों ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत सहित विभिन्न स्वच्छता संबंधी नारों के माध्यम से स्वच्छता एवं जागरूकता का संदेश दिया।

दीक्षारंभ कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए टैलेंट हंट एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया।

इस दौरान डॉ. प्रवीण वर्मा, सांस्कृतिक प्रभारी, कृषि महाविद्यालय, रायपुर ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनकी प्रतिभाओं एवं सांस्कृतिक रुचियों की जानकारी ली तथा उन्हें महाविद्यालय की विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

डॉक्टर गिरीश चंदेल, कुलपति, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, रायपुर एवं डॉ. आरती गुहे, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, रायपुर ने विद्यार्थियों को महात्मा गांधी जयंती की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने विद्यार्थियों को गांधी जी के स्वच्छता, अनुशासन, सत्य एवं सेवा के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया।

श्री बिरंचीनारायण मंदिर एवं नरसिंहनाथ मंदिर ट्रस्ट की जमीन का नामांतरण निरस्त

रायपुर। पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं एसडीएम ने कलेक्टर की अनुमति के बिना पुरानी बस्ती स्थित श्री बिरंचीनारायण मंदिर एवं नरसिंहनाथ मंदिर ट्रस्ट की जमीन की बिक्री को अवैध ठहराते हुए नामांतरण निरस्त करने का आदेश दिया। साथ ही दोषियों के खिलाफ एफआईआर के भी आदेश पारित किए। बताया जाता है कि आवेदक पंकज विश्वकर्मा ने प्राचीन बिरंचीनारायण मंदिर एवं नरसिंहनाथ मंदिर के स्वामित्व की धरमपुरा में 0.158 हेक्टेयर जमीन की अवैध खरीदो-बिक्री पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिकायत की थी। सीएम ने रायपुर कलेक्टर को जांच के लिए लिखा था। मंदिर सार्वजनिक न्यास के स्वामित्व की जमीन को ट्रस्टी अजय तिवारी के साथ मिलकर कलेक्टर और पंजीयक सार्वजनिक न्यास की अनुमति

के बिना बिक्री की गई। इस पूरे मामले एसडीएम कोर्ट ने प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किए। एसडीएम कोर्ट ने 29 सितंबर 2026 को जारी आदेश में ग्राम धरमपुरा स्थित खसरा नंबर 293/7, रकबा 0.158 हेक्टेयर की जमीन के विक्रय को विधि विरुद्ध माना गया है। कोर्ट ने जमीन के नामांतरण को निरस्त कर ट्रस्ट के नाम पर राजस्व अभिलेख दुरुस्त करने, विक्रय विलेख को शून्य कराने के लिए सक्षम सविल न्यायालय में कार्रवाई करने और संबंधित थाना प्रभारी को दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिकायत में बताया गया कि ट्रस्ट की बैठक में जमीन को 21 लाख रुपए में सौंप भेज और निखिल जैन के नाम से खरीदने का प्रस्ताव लिया गया था, लेकिन 1 दिसंबर 2022 को इसकी रजिस्ट्री घंशयाम दानी के नाम कराई गई।

पं. रविशंकर शुक्ल विवि में तीन साल बाद भी भर्ती अधूरी

रायपुर। राजधानी रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (पीआरएसयू) में तीन साल बीत जाने के बाद भी 111 प्राध्यापक पदों की भर्ती प्रक्रिया अधूरी पड़ी है। विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक केवल 52 पदों पर ही नियुक्तियां कर सका है, जबकि 59 पद अब भी खाली हैं। नियमित प्राध्यापकों की इस भारी कमी के कारण विश्वविद्यालय में पठन-पाठन और शोध कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इससे अध्ययनरत विद्यार्थियों और शोधार्थियों को निरंतर कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्राध्यापकों की इस भर्ती प्रक्रिया को दो अलग-अलग चरणों में

विभाजित किया था। प्रथम चरण के अंतर्गत 60 पदों के लिए प्रक्रिया आरंभ की गई थी, जिनमें से अब तक केवल 40 पदों पर ही नियुक्तियां हो सकी हैं। दूसरे चरण में 51 पदों को शामिल किया गया था, लेकिन इस चरण में विश्वविद्यालय मात्र 12 पदों पर ही भर्ती कर पाया है। दोनों चरणों को मिलाकर कुल 111 पदों में से 52 पद भरे जा चुके हैं और 59 पद आज भी रिक्त पड़े हैं।

नियमित शिक्षकों के पद रिक्त रहने से सबसे अधिक असर पीएचडी शोधार्थियों पर पड़ रहा है। विश्वविद्यालय में गाइड की उपलब्धता न होने के कारण शोध कार्य गति नहीं पकड़ पा रहे हैं। नियमित शिक्षकों के पद रिक्त रहने से सबसे अधिक असर पीएचडी शोधार्थियों पर पड़ रहा है। विश्वविद्यालय में गाइड की उपलब्धता न होने के कारण शोध कार्य गति नहीं पकड़ पा रहे हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा लगातार आगे बढ़ रही है। अगले 48 घंटे में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां बेहतर होने की संभावना जताई गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क दर्ज किया गया है।

एनआईबीएसएम में गांधी जयंती पर स्वच्छता पखवाड़े का समापन एवं सफाई मित्रों का सम्मान



रायपुर। भा.कृ.अनु.प-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, रायपुर में गांधी जयंती एवं स्वच्छता पखवाड़ा-2026 के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के दौरान स्वच्छता, स्वच्छ परिसर एवं स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों एवं सफाई अभियानों का आयोजन किया गया। समापन अवसर पर संस्थान में कार्यरत सफाई कर्मियों एवं सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व

प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया। संस्थान के निदेशक डॉ. पी. के. राय तथा संयुक्त निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।

इस अवसर पर डॉ. एस. के. शर्मा ने स्वच्छता पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पखवाड़े के दौरान संस्थान परिसर के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान, साफ-सफाई एवं जागरूकता संबंधी गतिविधियां संचालित की गईं।

बरसात के बाद सड़कों और पुलों के निर्माण को मिलेगी रफ्तार

रायपुर। बरसात के बाद प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण के कार्य तेजी से धरातल पर उतरेंगे। राज्य शासन ने इसके लिए तैयारियां पूरी करते हुए 672 करोड़ 22 लाख 30 हजार रूपए के 24 महत्वपूर्ण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें नई सड़कों और पुलों के निर्माण के साथ मौजूदा सड़कों के उन्नयन, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, विद्युतीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं। लोक

निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों को चयनित टेकदारों एवं निर्माण एजेंसियों को यथाशीघ्र कार्यादेश जारी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में मजबूत सड़क एवं पुल अधीसंरचना का निर्माण राज्य सरकार की

विकास प्राथमिकताओं में शामिल है। बेहतर सड़कें गांवों और शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य आवश्यक

सेवाओं तक लोगों की पहुंच को सुगम बनाती हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से आवागमन बेहतर होगा और व्यापार, पर्यटन सहित स्थानीय आर्थिक गतिविधियों की भी गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं का लाभ लोगों तक जल्द पहुंचे, इसके लिए कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए और निर्माण की गुणवत्ता की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।



कोल लेवी घोटाला : विधायक देवेंद्र यादव को एसीबी/ईओडब्ल्यू का नोटिस

■ विशेष कोर्ट में पेश होने के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी मामले में विधायक देवेंद्र यादव को मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी/ईओडब्ल्यू) ने उन्हें नोटिस जारी किया है। नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं का उल्लेख किया गया है। एसीबी/ईओडब्ल्यू की ओर से जारी नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7 और 12 का उल्लेख है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 420, 120-बी, 384, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज प्रकरण का भी



हवाला दिया गया है। नोटिस में बताया गया है कि अपराध क्रमांक 03/2024 में विवेचना के बाद अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाना है। यह अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

एसीबी/ईओडब्ल्यू के नोटिस के मुताबिक विधायक देवेंद्र यादव को 5 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।

छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई शुरू दो दिन और शुष्क रहेगा मौसम,

रायपुर। छत्तीसगढ़ से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटे के भीतर प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए स्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो सकती हैं। इस दौरान राज्य के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। विभाग ने फिलहाल प्रदेश के किसी भी जिले के लिए वर्षा या अन्य मौसम संबंधी अलर्ट जारी नहीं किया है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा लगातार आगे बढ़ रही है। अगले 48 घंटे में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां बेहतर होने की संभावना जताई गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क दर्ज किया गया है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी दो दिनों तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां काफी सीमित रहेंगी। राजधानी रायपुर में 2 अक्टूबर को मौसम साफ रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। इससे पूर्व गुरुवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। प्रदेश भर में तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो गुरुवार को राजनांदगांव में सबसे अधिक गर्मी दर्ज की गई, जहां अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके विपरीत पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे राज्य में सबसे कम रहा। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

बस्तर का दौरा करेंगे कांग्रेस प्रभारी भगत

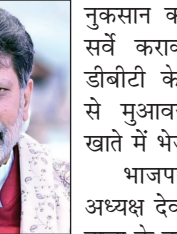
रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत 7 अक्टूबर को एक बार फिर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। दो दिवसीय दौरे में वह बस्तर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर जायजा लेंगे। साथ ही बाढ़ पीड़ितों से नुकसान को लेकर भी चर्चा करेंगे।

जानकारी के मुताबिक, 15 दिन के भीतर राज्य में उनका यह दूसरा दौरा होने वाला है। 7 से 9 अक्टूबर को वह बस्तर में रहेंगे। जहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही बाढ़ से प्रभावित हुए इलाकों में भी जाएंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर स्थिति की जानकारी लेंगे और प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि बीते दिनों मानसून सक्रिय होने के बाद लगातार मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ का बस्तर और बीजापुर पर इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने सीएम साय और केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र बस्तर बाढ़ विभीषिका के दृष्टिगत विशेष राहत पैकेज और दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने की मांग

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष सी.आर. पाटिल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने ओडिशा स्थित खातीगुड़ा बांध से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण बस्तर संभाग में उत्पन्न भीषण बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया है। छरू साय ने बस्तर के बाढ़ पीड़ितों के ताल्कालिक पुनर्वास, विशेष मुआवजा पैकेज, जोरा नाला की नई डीपीआर के निर्माण और दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन योजना की तत्काल स्वीकृति का आग्रह किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने केन्द्रीय मंत्री पाटिल को लिखे पत्र में ध्यान आकृष्ट किया है कि इंद्रावती जलाशय (खातीगुड़ा बांध) से अग्रिम चेतावनी और उचित समन्वय के बिना भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से इंद्रावती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। इसके चलते जगदलपुर शहर के कई

वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। लाखों एकड़ में लगी फसलें तबाह हो चुकी हैं, मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, मवेशी बह गए हैं और आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। अंतर्राज्यीय जल विनियमन के अभाव और जोरा नाला की भौगोलिक स्थिति और प्रभावी बाढ़ (आपदा) प्रबंधन के अभाव ने इस संकट को और अधिक गंभीर बना दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने पत्र में आपदा प्रभावितों के लिए विशेष मुआवजा एवं राहत पैकेज के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि बाढ़ से गृह हुई खरीफ फसलों के लिए किसानों को प्रति एकड़ के आधार पर एनडीआरएफ मद से विशेष राहत राशि तुरंत स्वीकृत की जाए। जिन परिवारों के कच्चे या पक्के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत प्राथमिकता से नया मकान और तत्काल जीवन-यापन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। बह गए मवेशियों, प्रभावित छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के



डीपीआर निर्माण और कार्यान्वयन को जरूरी बताते हुए कहा है कि जोरा नाला में अनियंत्रित कटाव और इंद्रावती नदी के जल विचलन (वाटर डायवर्सन) को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन कराकर नया और संशोधित डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किया जाए। इसी तरह जोरा नाला पर एक स्वचालित आधुनिक 'गेटेड रेगुलेटर स्ट्रक्चर' बनाया जाए, ताकि मानसून के दौरान अतिरिक्त जलप्रवाह को वैज्ञानिक तरीके से इंद्रावती और जोरा नाला के बीच विभाजित कर बस्तर पर बाढ़ के सीधे दबाव को कम

किया जा सके।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने बाढ़ प्रबंधन प्लान एवं कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट की जरूरत पर बल देते हुए कहा है कि इंद्रावती और उसकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पौधरोपण, मुदा संरक्षण और कंट्रू ट्रेचिंग का कार्य किया जाए, जिससे रन-ऑफ वाटर की गति और गाद का जमाव रुक सके। इसके लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के तकनीकी मार्गदर्शन में इंद्रावती नदी के तल में वर्षों से जमी गाद को हटाने के लिए ड्रेजिंग प्रोजेक्ट स्वीकृत किया जाए, ताकि नदी की जलधारण क्षमता बढ़ सके। जगदलपुर अर्बन ड्रेनेज और टाउन प्लानिंग का उल्लेख कर देव ने कहा कि जगदलपुर शहर के लिए अमृत (एएमआरयूटी) योजना के अंतर्गत 'एकीकृत स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम' विकसित किया जाए और नदी के संवेदनशील तटवर्ती इलाकों में पक्के गाइड बांध/तटबंध बनाए जाएं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने पत्र में कहा है कि ओडिशा के खातीगुड़ा बांध से पानी छोड़े जाने के समय और मात्रा का रियल-टाइम टेलीमेट्री डेटा छत्तीसगढ़ प्रशासन के साथ साझा करने के लिए केंद्रीय जल आयोग को नोडल एजेंसी बनाया जाए। इंद्रावती बेसिन में सेंसर-आधारित चेतावनी प्रणालियां स्थापित की जाएं, जिससे पानी छोड़े जाने से कम-से-कम 24 से 48 घंटे पूर्व निचले इलाकों को खाली कराया जा सके।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बस्तर का यह क्षेत्र मुख्य रूप से गरीब और जनजातीय आबादी से आच्छादित है, जो इस विनाशकारी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अतः परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार की एक अंतर-मंत्रालयीन अध्ययन टीम तुरंत भौतिक सत्यापन के लिए बस्तर भेजी जाए और 'विशेष बस्तर बाढ़ राहत, जोरा नाला डीपीआर एवं पुनरुद्धार पैकेज' को अविलंब स्वीकृति प्रदान की जाए।

एडीआर डाटा: दलबदल के दलदल में धंसता लोकतंत्र

राजकुमार सिंह

चुनाव सुधारों के उद्देश्य से आईआईएम (अहमदाबाद) के प्रोफेसरों द्वारा 1999 में बनाई गई गैरपक्षपाती संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के आंकड़े बताते हैं कि 2022 से अब तक 111 सांसद-विधायक दलबदल कर चुके हैं। दलबदल की बढ़ती बीमारी के लिए किसी एक दल को दोष नहीं दिया जा सकता, पर इससे राजनीतिक लाभ से परहेज भी किसी ने नहीं किया।

भाजपा 12 साल से केंद्र में सत्तारूढ़ है। ज्यादातर राज्यों में भी भाजपा या राजग की सरकारें हैं। आम धारणा के मुताबिक दलबदल के इस खेल से सर्वाधिक लाभान्वित भाजपा होनी चाहिए, पर पिछले चार साल में दलबदल से लाभान्वित दलों में भाजपा दूसरे नंबर पर है। सर्वाधिक लाभान्वित दल नगालैंड में सत्तारूढ़ नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) है, जिसे इस अवधि में 32 विधायक मिले। दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः भाजपा और एनसीपीआई रहें। दलबदल से लाभान्वित राज्यों में पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है, जहां 20 सांसदों ने दल बदल लिया। लाभार्थी के रूप में दिमाग में फिर भाजपा का ही नाम आया होगा, पर आंकड़े कई बार पूरा सच नहीं बताते। विधानसभा चुनाव के बाद तुणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने अपने दल से दगा किया, पर सीधे ‘कमल’ थामने के बजाय अल्पज्ञात एनसीपीआई चुनी। चार राज्यसभा सांसदों ने भी तुणमूल से दगा किया, लेकिन संसद सदस्यता से इस्तीफे की ‘नैतिकता’ दिखाई, जिसका सच भी भाजपा द्वारा उन्हें उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने से बेनकाब हो गया।

एडीआर के ताजा आंकड़े सांसदों-विधायकों के 2022 के बाद दलबदल के ही हैं, लेकिन यह बीमारी दशकों पुरानी है। नेताओं का दिल बदलने का पता भी दूसरे दल का पट्टा गले में पहनने के बाद ही चलता है। नेताजी इस अवसरवाद को देश, समाज और लोकतंत्र के हित में ‘जरूरी’ करार देते हैं, पर यह सवाल अनुत्तरित है कि फिर अब तक देश, समाज और लोकतंत्र का अहित क्यों करते रहे? बड़े नेताओं के दलबदल की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनाव बताते हैं कि यह बीमारी बहुत नीचे तक पहुंच चुकी है। भाजपा-कांग्रेस जैसे बड़े दलों में भी बगावत, बड़ी संख्या में निर्दलीयों के रूप में बागियों की जीत और फिर उन्हें वापस गले लगाने की कवायद भारतीय राजनीति की विदुरूप तस्वीर पेश करती है। जो बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत गए, उन्हें टिकट देने लायक नहीं समझा तो यह दलों के संचालन और आंतरिक लोकतंत्र पर भी सवालिया निशान है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिला भरतपुर में भाजपा मात्र 20 सीटें जीत पाई, जबकि 38 निर्दलीय जीत गए। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) छात्र संघ का उदाहरण भी देखें। जिस दीपांशु शौकीन को कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार लायक नहीं समझा, उसने रिकॉर्ड 30 हजार से भी ज्यादा वोट और 13 हजार से भी ज्यादा अंतर से जीत हासिल की। फिर आश्चर्य कैसा कि एक दशक में पहली बार डीयू में एनएसयूआई का खाता नहीं खुला और स्थानीय निकाय से ले कर विधानसभा उपचुनाव तक में कुछ राष्ट्रीय नेता अपना वार्ड और बूथ तक हार गए। जब तक राजनीतिक दल तात्कालिक लाभ के लिए दलबदलुओं पर दांव लगाते रहेंगे, लोकतंत्र दलबदल के दलदल में धंसता रहेगा।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

11- भारतीय दर्शन और योग

गतांक से आगे...

आलोचनात्मक विचार करने से यह पता चलता है कि बौद्धदर्शन का योग के साथ प्रारम्भ से ही इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है जितना कि कदाचित् किसी वैदिक दर्शन का भी न हो। पातञ्जल योगसूत्रों पर व्यासभाष्य जो कि योग का आधारभूत ग्रन्थ है, बौद्ध प्रभाव से अत्यन्त प्रभावित प्रतीत होता है उसके अनेक शब्द बौद्ध सम्प्रदायों के ही शब्द हैं। यहां पर हमें केवल इतना ही कहना है कि यद्यपि योग छै वैदिक दर्शनों में से एक है; परन्तु वस्तुतः योग कोई दार्शनिक मत नहीं है, प्रत्युत योग का अभ्यास कई वैदिक और अवैदिक दार्शनिक सम्प्रदायों के साथ सम्बद्ध है। वर्तुमान समय में वैदिक छै दर्शनों में जो पातञ्जल योगदर्शन गिना जाता है वह सांख्य सम्प्रदाय से सम्बद्ध योग है, अर्थात् जैसा कि ऊपर कहा गया है, उसके दार्शनिक सिद्धान्त सांख्य के ही हैं, परन्तु जहां तक क्रियात्मक योग प्रक्रिया का प्रश्न है सभी

दार्शनिक सम्प्रदायों के योग की प्रक्रिया पतञ्जलि की योग-प्रक्रिया से मिलती जुलती थी, यह स्पष्ट है।

12 प्रकीर्ण दार्शनिक सम्प्रदाय

ऊपर हमने जिन दार्शनिक सम्प्रदायों का उल्लेख किया है, उनसे अतिरिक्त अनेक अन्य भी दार्शनिक सम्प्रदाय थे, उदाहरणार्थ, माधवाचार्य के प्रसिद्ध ग्रन्थ सर्वदर्शनसंग्रह में उपयुक्त प्रसिद्ध दार्शनिक सम्प्रदायों के सिवाय पूर्णप्रज्ञदर्शन, नकुलीपाशुपतदर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, रसेश्वरदर्शन आदि अनेक दार्शनिक सम्प्रदायों का वर्णन है। यहां तक कि पाणिनि का दर्शन भी एक अलग दार्शनिक सम्प्रदाय के रूप में दिखाया गया है।

यह स्पष्ट है कि इसके अतिरिक्त भी अनेक दार्शनिक सम्प्रदाय थे, उदाहरणार्थ, द्वैतवादी माध्वों का भी एक अलग दार्शनिक सम्प्रदाय था, यद्यपि उसका वर्णन सर्वदर्शनसंग्रह में नहीं है।

क्रमशः ...



ओशो

मनुष्य को सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह अपने जीवन को जीने से पहले ही किसी और के हाथों में सौंप देता है। वह कहता है कि जो भाग्य में लिखा है, वही होगा। और, यह छोट्टा-सा वाक्य धीरे-धीरे उसके जीवन का दर्शन बन जाता है। फिर, वह अपने फैसलों के लिए परिस्थितियों को दोष देने लगता है और असफलताओं के लिए भाग्य को कोसता है। लेकिन, क्या सचमुच कोई भाग्य तुम्हारे जीवन को लिख रहा है! अगर सब कुछ पहले से लिखा है, तो फिर तुम्हारे चुनाव और कर्म का क्या अर्थ रह जाता है? तुम्हारे प्रेम और साहस का क्या होता है? तुम्हारे भीतर उठती हुई उस आवाज का क्या अर्थ है, जो कहती है कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ? भाग्य पर भरोसा अक्सर मनुष्य को

जीवन को भाग्य के हवाले मत करो



एक अदृश्य सातवना देता है। तब वह कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता था, ऐसा ही होना था। इस तरह वह अपने जीवन की जिम्मेदारी से बच जाता है। जीवन कोई तैयार किताब नहीं, जिसके हर पन्ने पर पहले से शब्द लिखे हों। जीवन तो खाली पन्नों की तरह है। परिस्थितियां तुम्हें कागज देती हैं, पर शब्द तुम्हें ही लिखने होते हैं। जीवन तो जिम्मेदारी है। हवाएं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन नाव की दिशा तुम्हें ही तय करनी है। रास्ते हमेशा

तुम्हारे अनुसार नहीं होंगे, किंतु चलना या रुक जाना तुम्हारे हाथ में है। हालांकि, यह भी सच है कि बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था। मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है। मौसम तुम्हारे हाथ में नहीं है। दूसरे मनुष्य तुम्हारे अनुसार व्यवहार करें, यह भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। मनुष्य का एक बड़ा भ्रम है कि जीवन कल से शुरू होगा। जीवन का अर्थ अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करना नहीं है। उसका अर्थ है प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी अपनी चेतना को जीवित रखना। तुम्हें जीवन ने जो दिया है, उससे तुम क्या बनाते हो, यही सृजन है। एक ही परिस्थिति में दो मनुष्य होते हैं। एक व्यक्ति असफल होकर कहता है कि

मेरे भाग्य में सफलता नहीं थी। दूसरा कहता है कि यह असफलता मुझे कुछ सिखाने आई है। पहला व्यक्ति असफलता को ही अंतिम निर्णय बना देता है, जबकि दूसरा उसे अगला कदम। यही अंतर है। इसलिए, जीवन को भाग्य की नहीं, संभावना की दृष्टि से देखो। मनुष्य को सबसे अधिक स्वतंत्रता तब मिलती है, जब वह यह समझ लेता है कि उसे अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी है। यह जिम्मेदारी बोझ नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है।

जीवन तुम्हारी इच्छाओं का गुलाम नहीं है। तुम्हारे पास जीवन में घटित होने वाली हर घटना को नियंत्रित करने की शक्ति भी नहीं है, पर हर घटना के बाद अपने भीतर क्या बचाए रखना है, यह तुम ही तय करते हो। इसलिए, भाग्य से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस कम करो और अपने जीवन को भाग्य के हवाले मत करो।

निरंज कुमार दुबे

अमेरिका अब किसी विदेशी नागरिक को अपने देश से बाहर निकालने के लिए उसके मूल देश के दरवाजे पर दस्तक देने और वहां से हरी झंडी मिलने का इंतजार नहीं करता। ट्रंप प्रशासन ने निर्वासन की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। जिस व्यक्ति को अमेरिका से बाहर करना है, उसका देश उसे वापस लेगा या नहीं, इस बात पर अब अमेरिका माथापच्ची करने में समय नहीं गंवाता। अमेरिका अब खुद उसके लिए कोई तीसरा ठिकाना तलाश रहा है और उसे वहां पहुंचाने के लिए अपनी तिजोरी से धन खर्च कर रहा है। यानी जिस व्यक्ति को अमेरिका नहीं रखना चाहता, उसे उसके अपने देश में भेजने की बजाय किसी ऐसे देश में धकेला जा रहा है, जिससे उसका कोई नाता तक नहीं है। इस पूरी कवायद में अमेरिका उन देशों को पैसा भी दे रहा है, ताकि वे इन लोगों को अपने यहां रखने के लिए तैयार हो जाएं। यह केवल निर्वासन नहीं, बल्कि अमेरिकी धन, कूटनीतिक दबाव और वैश्विक प्रभाव के सहारे खड़ा किया जा रहा एक ऐसा तंत्र है, जिसमें अमेरिका तय कर रहा है कि उसके यहां से निकाला गया व्यक्ति आखिर दुनिया के किस कोने में पहुंचेगा।

देखा जाये तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की आब्रजन नीति अब केवल सीमा बंद करने, गिरफ्तारी और निर्वासन तक सीमित नहीं रह गई है। अमेरिकी समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक पड़ताल में जो खुलासा किया है उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी विदेश विभाग के जिस तंत्र का मूल काम दुनिया भर से उत्पीड़ित लोगों को शरण और पुनर्वास दिलाना था, उसी को अब दूसरे देशों में लोगों को धकेलने वाली एक विशाल निर्वासन व्यवस्था में बदल दिया गया है। इस पूरी कवायद के लिए कम से कम 410 करोड़ डॉलर की राशि स्वीकृत या प्रतिबद्ध की जा चुकी है और 31 देशों के साथ समझौते किए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में विदेश विभाग के भीतर बनाया गया नया कार्यालय है। इसका नेतृत्व क्रिश्चियन एरहार्ट कर रहे हैं, जो पहले करीब दो दशक तक अमेरिकी दूतावासों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े रहे थे। अब वही अधिकारी अफ्रीका और दूसरे क्षेत्रों में घूम-घूमकर सरकारों को ऐसे लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार कर रहे हैं, जिनका उन देशों से



कोई संबंध तक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियन एरहार्ट को कई विदेशी सरकारों के सामने सामान्य अधिकारी नहीं, बल्कि सीधे व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनके पीछे ट्रंप प्रशासन के प्रभावशाली अधिकारी स्टीफन मिलर की निर्णायक भूमिका बताई गई है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका इन देशों को केवल कूटनीतिक दबाव से नहीं मना रहा, बल्कि भारी आर्थिक प्रोत्साहन भी दे रहा है। कम से कम 81 करोड़ डॉलर सीधे 13 विदेशी सरकारों को देने की प्रतिबद्धता सामने आई है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के लिए 179 करोड़ डॉलर और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संस्था के लिए 124 करोड़ डॉलर की राशि का प्रावधान किया गया है। इन संस्थाओं को इन समझौतों का प्रत्यक्ष पक्ष नहीं बताया गया है, लेकिन संबंधित देशों को निर्वासित लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया में इन पैसों को प्रोत्साहन के रूप में इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है।

यानी तत्वीर बेहद साफ है। जिस व्यवस्था में कभी अमेरिका दूसरे देशों से भागकर आए लोगों को सुरक्षित जीवन देने के लिए धन लगाता था, अब उसी धन का इस्तेमाल ऐसे देशों को तैयार करने में हो रहा है जो अमेरिका से निकाले गए लोगों को अपने यहां रखने के लिए राजी हों। ट्रंप प्रशासन ने शरणार्थी पुनर्वास की पुरानी दिशा को पलटकर उसे निर्वासन केंद्रित बना दिया है। प्रशासन के अपने एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया है कि संबंधित विभाग की दिशा पूरी तरह बदल दी गई है।

बताया जा रहा है कि कोस्टा रिका भेजी गई उड़ानों में चीन, रूस, ईरान और अफगानिस्तान के

लोग थे। इस्वातिनी भेजे गए लोगों में वियतनाम, लाओस, क्यूबा और जमैका के नागरिक शामिल थे। युगांडा केवल अफ्रीकी नागरिकों को लेने पर सहमत हुआ, जबकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने अफ्रीकी नागरिकों को ही स्वीकार करने से इंकार कर दिया। कुछ देश गंभीर

अपराधों के आरोपियों को भी लेने के लिए तैयार हैं, जबकि कुछ ने अपराध की प्रकृति के आधार पर सीमाएं तय की हैं।

अब तक 25 हजार से अधिक लोगों को कम से कम 28 तीसरे देशों में भेजे जाने का अनुमान है। इनमें करीब 20 हजार लोग मेक्सिको भेजे गए। बाकी लोगों को मुख्यतः अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में धकेला गया। अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि इनमें ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अतिम निर्वासन आदेश हैं, लेकिन उनके अपने देश उन्हें वापस लेने से इंकार करते हैं या उन्हें वहां भेजने पर उत्पीड़न का खतरा है। प्रशासन का दावा है कि तीसरे देश का रास्ता ऐसे कठिन मामलों को निपटाने का साधन है।

लेकिन यहीं से इस नीति का सबसे गंभीर कानूनी पक्ष शुरू होता है। अलोचकों और आब्रजन वकीलों का आरोप है कि तीसरे देश में भेजकर वहां से संबंधित व्यक्ति को उसके मूल देश में जबरन भेजे जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून में ऐसे स्थान पर भेजना जहां व्यक्ति को उत्पीड़न या यातना का खतरा हो, गंभीर कानूनी सवाल खड़े करता है। गत शुक्रवार को एक संघीय अपीली अदालत ने इस नीति को गैरकानूनी ठहराते हुए कहा कि प्रभावित लोगों को तीसरे देश में भेजे जाने से पहले पर्याप्त सूचना और अपने भय या खतरे से जुड़े दावे रखने का अवसर नहीं दिया गया। हालांकि प्रशासन से इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, पनामा का मामला इस पूरी व्यवस्था को असली तस्वीर दिखाता है। जनवरी 2025 में अमेरिका ने 299 लोगों को पनामा भेजा, जबकि उनका पनामा से कोई संबंध नहीं था।

बिना प्रमाण के आरोप लगाना ठीक नहीं

सुरेश हिंदुस्तानी

राजनीति केवल आलोचना करने का नाम नहीं, बल्कि एक सकारात्मक चिंतन प्रवाह और देश को सही राह पर ले जाने के लिए किए जाने वाला प्रयास है। लेकिन आज हमारे देश में राजनीति का पर्याय केवल आरोप लगाने तक ही सीमित होता दिखाई दे रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरोप हमेशा सच नहीं होते हैं। प्रमाण के साथ आरोप लगाने की राजनीति की जाए तो उसका महत्व समझ में आता है, लेकिन बिना प्रमाण के आरोप लगाना देश की जनता को गुमराह करने जैसा ही कृत्य माना जाएगा। वर्तमान में कुछ इसी प्रकार की राजनीति की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस प्रकार की राजनीति देश के विकास के लिए उचित कही जा सकती है। बिलकुल नहीं।

हालांकि यह सर्वथा सत्य है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की अपनी-अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। दोनों को बिना प्रमाण के आरोप लगाने की परिधि से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन यह हो सकेगा, ऐसा संभव नहीं दिख रहा। विपक्ष का दायित्व केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर उसकी नीतियों की समीक्षा करना और जनता के सामने वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करना भी है। दुर्भाग्य से आज की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का शोर इतना बढ़ गया है कि तथ्य और प्रमाण पीछे छूटते दिखाई देते हैं। किसी व्यक्ति, संस्था अथवा सरकार पर गंभीर आरोप लगा देना आसान है, लेकिन उन आरोपों को प्रामाणित करना ही लोकतांत्रिक राजनीति की वास्तविक कसौटी है। आरोप लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आरोप अपने आप में प्रमाण नहीं होते। किसी व्यक्ति पर आरोप लगा देने मात्र से वह अपराधी नहीं हो जाता। कानून और लोकतांत्रिक मर्यादा दोनों यही कहते हैं कि आरोप की जांच हो, प्रमाण सामने आए और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। सार्वजनिक जीवन में यह जिम्मेदारी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नेताओं के बयान



समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं। बिना प्रमाण के लगाए गए आरोप व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास को भी कमजोर कर सकते हैं। हाल के राजनीतिक विमर्श में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को लेकर लगाए गए आरोप इसी संदर्भ में चर्चा का विषय बने हैं। विपक्ष की ओर से चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चुनाव आयोग ने भी विभिन्न अवसरों पर आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने की बात कही है। ऐसे मामलों में लोकतांत्रिक तरीका यही होना चाहिए कि यदि किसी संस्था या अधिकारी के विरुद्ध कोई ठोस तथ्य उपलब्ध है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, संबंधित संवैधानिक संस्था के समक्ष रखा जाए और निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से उसकी जांच कराई जाए। केवल राजनीतिक मंचों से आरोप दोहराते रहने से किसी आरोप की सत्यता स्थापित नहीं होती।

कांग्रेस द्वारा इस विषय पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाना भी राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा है। विपक्षी दलों को सरकार और संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन सवालों की गंभीरता उनकी संख्या से नहीं, बल्कि उनके पीछे मौजूद प्रमाणों और तथ्यों से तय होती है। यदि आरोप गंभीर हैं तो उनके समर्थन में ठोस सामग्री भी उतनी ही गंभीर होनी चाहिए।

यही स्थिति उद्योग जगत के प्रमुख नामों अड़ानी और अंबानी को लेकर लगाए जाने वाले आरोपों पर भी लागू होती है। किसी उद्योगपति का सरकार से

संबंध होने का आरोप अलग बात है और किसी सरकारी निर्णय में अवैध लाभ पहुंचाने का प्रमाण होना अलग बात है। व्यावसायिक लेन-देन, कंपनियों की खरीद, निवेश और संपत्तियों का अधिग्रहण अपनी निर्धारित कानूनी और कारोबारी प्रक्रियाओं के अंतर्गत होते हैं। यदि किसी सौदे को लेकर आपति है तो उसके दस्तावेज, वित्तीय विवरण और नियामकीय रिकॉर्ड सामने रखे जाने चाहिए। केवल किसी कारोबारी समूह का नाम लेकर राजनीतिक आरोप लगाना तथ्यात्मक बहस का विकल्प नहीं हो सकता।

यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि यदि भारतीय उद्योग समूह किसी ऐसी संपत्ति अथवा कंपनी का अधिग्रहण करते हैं, जो पहले किसी विदेशी कंपनी के स्वामित्व में थी, तो क्या केवल इसलिए इसे संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि खरीदार भारतीय है? यदि कोई भारतीय उद्यमी वैश्विक स्तर पर विस्तार करता है, विदेशी संपत्ति या कंपनी का अधिग्रहण करता है और वह प्रक्रिया कानून के अनुरूप होती है, तो इसे भारतीय उद्योग की वैश्विक क्षमता के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि किसी भी कारोबारी सौदे में पारदर्शिता और नियामकीय अनुपालन की जांच आवश्यक है। आलोचना का आधार तथ्य होना चाहिए।

राजनीति में सबसे बड़ी समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी दल का पूरा राजनीतिक विमर्श किसी एक व्यक्ति या नेता के विरोध तक सीमित दिखाई देने लगे। विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना अवश्य है, लेकिन जनता यह भी जानना चाहती है कि विपक्ष सत्ता में आने पर क्या करेगा। स्पष्ट वैकल्पिक नीतियां लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को सार्थक बनाती हैं। केवल विरोध की राजनीति लंबे समय तक जनता को आकर्षित नहीं कर सकती। यह भी ध्यान देने योग्य

आज का इतिहास

- 1735 फ्रांस और छठे कैरल सम्राट ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- 1831 मैसूर (अब मैसुरु) पर ब्रिटेन ने कब्ज़ा किया।
- 1880 पहले मराठी संगीत नाटक ‘संगीत शाकुन्तल’ का पुणे में मंचन किया गया।
- 1915 नेवादा के प्लेजेंट वैली में 7.8 रिक्टर पैमाने का भूकंप आया।
- 1927 पी. परमेश्वरन – जनसंघ के पूर्व उपाध्यक्ष, दिग्गज लेखक, कवि और प्रसिद्ध संघ विचारक का जन्म हुआ।
- 1932– इराक यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ।
- 1967 भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ गजेंद्र सिंह शेखावत का जन्म हुआ।
- 1977 पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
- 1978 कलकत्ता (अब कोलकाता) में पहला और दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ।
- 1984 भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तक के लिए रवाना की गयी।
- 1992 गीत सेठी ने विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप जीता।
- 1994 भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया।
- 1995 चीन एवं इंग्लैंड के बीच हांगकांग के सुाम हस्तांतरण पर सहमति।
- 1996 पाकिस्तान के 16 वर्षीय बह्बेबाज शाहिद अफरीदी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 37 गेंदों में शतक बनाकर विश्व कीर्तिमान का।
- 1999 आण्विक पदार्थों के आवागमन और आण्विक दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सं.रा. अमेरिका तथा रूस ने संयुक्त संकट केन्द्र की स्थापना की।
- 2002 नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अमेरिका के राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को संयुक्त रूप से देनी की सिफारिश की गई।
- 2003 पाकिस्तान ने हल्फ-III मिसाइल का परीक्षण किया।
- 2004 लश्कर-ए-तैयबा के राजनीतिक संगठन दो हिस्सों में बंटा।
- 2006 संयुक्त राष्ट्र संघ के नये महासचिव दक्षिण कोरिया के बान की मून होंगे।
- 2008 टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा ने सिंगूर से नैनो कार परियोजना अन्यत्र ले जाने की घोषणा की।
- 2013 इतालवी द्वीप लातेदुसा के पास एक नाव के डूब जाने से करीब 134 लोगों की मौत हो गई।

फ्लायदुबई : घायल कैप्टन और साहसी यात्रियों की सूझबूझ ने बचाई आतंकी घटना!

रजनीश कपूर

9/11 जैसी आतंकी दुर्घटना 25 साल बाद फिर सितंबर महीने में होती पर भारतीय मूल के पायलट की सूझबूझ से 174 यात्रियों की जान बच गई जिनमें 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक थे। आज वे इजराइल के हर नागरिक की नजर में एक हीरो हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस जांबाज पायलट कैप्टन स्मिट मच्छर से मिलकर शाबाशी दी और गले लगाया। ए्विएशन के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व घटना है। जब कॉकपिट में बैठे को-पायलट ने मुख्य पायलट पर धारदार हथियार से हमला किया और उसे लहलूहान कर दिया।

30 सितंबर 2026 को, दुबई से तेल अवीव जा रही ‘फ्लाय दुबई’ की उड़ान एफजेड 1073 लगभग सामान्य लग रही थी। बोइंग 737 में करीब 174 यात्री सवार थे। उड़ान के दूसरे घंटे के आसपास कॉकपिट में वह हुआ, जिसकी कल्पना यात्री शायद ही करते हों। इजरायली अधिकारियों और यात्रियों के बयानों के अनुसार, ओमानी नागरिक बताए जा रहे को-पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मिट मच्छर पर चाकू से जानलेवा हमला किया और विमान के नियंत्रण पर कब्जा करने की कोशिश की। विमान अचानक तेज गोता लगाने लगा।

ट्रैकिंग ऑंकड़ों के हवाले से यह कहा गया है कि कुछ ही क्षणों में ऊंचाई कई हजार फीट गिर गई। घायल कप्तान ने लड़ते हुए कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिससे यात्री और चालक दल हमलावर को काबू कर सके और एक भयंकर हवाई त्रासदी टल गई।

हमलावर का मकसद, चाकू का कॉकपिट में पहुंचना

और अलार्म की पूरी श्रृंखला अभी जांच के अधीन है। एयरलाइन ने पायलटों की पहचान सार्वजनिक नहीं की थी। उनके नाम इजरायली मीडिया, अधिकारियों और बाद में भारतीय दूतावास के बयानों से सामने आए। हादसे के बाद कैप्टन स्मिट सऊदी अरब के तबूक अस्पताल में स्थिर बताए गए हैं। फिर भी जो बात अब तक के बयानों से साफ है, वह साहस और सूझबूझ की परिभाषा बदल देती है। साहस हमेशा विमान को अकेले उतार लेने का नाम नहीं होता। कभी-कभी साहस खून से लथपथ होकर भी उस एक स्विच तक पहुंचने का नाम होता है, जिससे बाकी लोग अंदर आ सकें।

कैप्टन स्मिट मुंबई से एक भारतीय पायलट हैं। भारत की एक निजी एयरलाइन में कई साल रहने के बाद जून 2022 में फ्लाय दुबई में डायरेक्ट-एंट्री के द्वारा कैप्टन बने और बोइंग 737 पर हजारों घंटे की कमान संभाली है। प्रशिक्षण कप्तान के रूप में उनका काम दूसरों को विमान उड़ाना सिखाना था। लेकिन कल उन्होंने खुद को सिखाया हुआ सबसे कठिन पाठ दोहराया जब सिस्टम टूटने लगे, तो इंसान की प्राथमिकता विमान को लोगों के हवाले करना है, न कि अकेले नायक बने रहना।

गौरतलब है कि कॉकपिट का दरवाजा जान-बूझकर ऐसा बनाया जाता है कि बाहर से आसानी से न खुले। अमरीका में हुए 9/11 हमले के बाद यही डिजाइन हवाई सुरक्षा की रीढ़ बना। उसी डिजाइन ने कल एक विरोधाभास पैदा किया। अगर कप्तान बेहोश हो जाते और दरवाजा बंद रहता, तो बाहर खड़े यात्री चाहे कितने भी बहादुर होते, अंदर नहीं पहुंच पाते। यात्री यानिव हायून्, जिन्हें प्लंबर बताया गया, ने बाद में कहा कि दरवाजा



उनके पहुंचने पर खुला था और उनका अनुमान है कि घायल कप्तान ने गिरने से पहले उसे खोल दिया।

इजरायली प्रवक्ता के हवाले से यह भी कहा गया कि कैप्टन स्मिट ने बची हुई ताकत के आखिरी क्षणों में रिलीज का बटन दबाया। यह सूझबूझ की पहचान है। याव की पीड़ा, खून और विमान के गोता लगाने का शोर, इन सबके बीच दिमाग ने वह काम चुना जो सामूहिक बचाव को संभव बनाता है। नेतन्याहू ने इसे 9/11 जैसी आपदा रोकने वाली बहादुरी कहा। जांच चाहे जो भी निष्कर्ष दे, इस क्षण की कीमत कम नहीं होती।

वहीं इस कहानी में साहसी यात्रियों का योगदान भी सराहनीय है। हायून् ने हमलावर को पकड़ा, गला दबाकर नियंत्रण पैनल से दूर खींचा और फिर उन लीवरों की खींचा जो उन्होंने एयर-क्रैश संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में देखे थे। विमान में सवार ऑफ-ड्यूटी पायलटों ने बाद में नियंत्रण संभाला और तबूक में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। एक दंत चिकित्सक यात्री ने कप्तान का खून रोकने में मदद की। चार-पांच अनजान लोगों ने मिलकर

वह काम किया, जिसके लिए कोई प्रशिक्षण मैनुअल केबिन में नहीं बांटा जाता। विमान सुरक्षित उतरा और सभी यात्री बच गए।

हम पायलट की वीरता के गीत गाते हैं और गाने भी चाहिए। लेकिन क्या हम यात्री के रूप में खुद को केवल सीट बेल्ट बंधने वाला उपभोक्ता मानकर चलते हैं? कल की उड़ान ने दिखाया कि कॉकपिट की दीवार के बाहर भी फैसले लिए जाते हैं। जो यात्री आगे की ओर दौड़े, उन्होंने घबराहट में चिल्लाकर गलियारा नहीं रोका। जिन्होंने हमलावर को दबाए रखा, उन्होंने कैमरा निकालकर वीडियो नहीं बनाया। यह फर्क प्रशिक्षण से कम, मानसिक तैयारी से ज्यादा आता है।

यात्री जागरूकता का मतलब हर व्यक्ति का कमांडो बनना नहीं है। बल्कि आपात स्थिति में तीन बातें पहले से पता हों। पहली, एग्जिट कहाँ हैं और वे कैसे खुलते हैं, सुरक्षा प्रदर्शन के दौरान फ़ोन देखना बाद में महंगा पड़ सकता है। दूसरी, अचानक गोता या तेज झुकाव में अपनी सीट पर टिके रहना और दूसरों को भी वही करने देना, क्योंकि अव्यवस्थित भीड़ कॉकपिट तक पहुंचने वाले लोगों का रास्ता रोक देती है।

तीसरी, अगर कॉकपिट से संघर्ष की आवाज आए और दरवाजा खुले, तो निर्णय का क्षण बहुत छोटा होता है। भीड़ में से कुछ लोगों का आगे बढ़ना, बाकी का रास्ता देना और हमलावर को नियंत्रण से दूर रखना। ऐसा ही कुछ कल हुआ। हायून् ने स्वीकार किया कि उन्होंने टेलीविजन पर देखे नियंत्रण खींचे। यह आदर्श प्रशिक्षण नहीं है। फिर भी शून्य से बेहतर है। एयरलाईंस और नियामकों को केबिन करू के साथ यात्रियों के लिए छोटे, वास्तविक अभ्यासों पर गंभीरता से सोचना चाहिए।

कमला हैरिस बिल्कुल वही कर रही हैं जो उनकी पार्टी उनसे चाहती है

निया-मलिका हेंडरसन

जब मैंने सुना कि अमरीका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मिशगिन में डेमोकेटिक सीनेट उम्मीदवार अब्दुल अल-सईद के साथ चुनाव प्रचार में शामिल होने जा रही हैं, तो मैंने उनसे तारह की जोशोली और विशाल रैलियों की कल्पना की, जो उनके 107 दिनों के व्हाइट हाउस अभियान की पहचान थीं। इसकी बजाय, हैरिस डेर्ट्रॉयट में अफ्रीकी-अमरीकी मातृ स्वास्थ्य गोलमेज सम्मेलन (राउंडटेबल) कार्यक्रम में अल-सईद के साथ नजर आईं। यह डेमोकेटिक वोट बैंक के उन हिस्सों को साधने के अल-सईद के प्रयासों का संकेत था, जिन्होंने उनके प्राइमरी प्रतिद्वंद्वी हेली स्टीवरस को प्राथमिकता दी थी। यह इस बात का भी संकेत था कि हैरिस—जिनके बारे में कहा जाता है कि वे व्हाइट हाउस के लिए तीसरी बार दावेदारी पर विचार कर रही हैं—यदि 2028 में चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं, तो उनके लिए केवल एक सीमित दायरे (विशिष्ट वर्ग) की उम्मीदवार से आगे निकल पाना कठिन होगा। हालाँकि हैरिस को उन अफ्रीकी-अमरीकी मतदाताओं के बीच बढ़त मिल सकती है जिनकी अल-सईद की मिशगिन में सीनेट चुनावी जीतने के लिए जरूरत है—जैसे कि अफ्रीकी-अमरीकियों में उम्रदराज मतदाता और महिलाएं—लेकिन यह ताकत उनकी अपनी खुद की जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। मिशगिन में उनकी मौजूदगी और इस साल अन्य डेमोकेटिक उम्मीदवारों द्वारा उनसे बनाई जा रही दूरी, इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि हैरिस संभवतः राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल नहीं होंगी। और सच कहें तो, यदि इस अनुकूल मध्यावधि चक्र में भी पार्टी द्वारा उन्हें व्यापक

रूप से स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो उन्हें चुनाव लड़ना भी नहीं चाहिए। हैरिस स्पष्ट रूप से यह दिखाना चाहती हैं कि वे—और व्यापक रूप से वे मतदाता जो उन्हें सबसे अधिक पसंद करते हैं—2026 में डेमोकेट्स को जीतने में मदद कर सकते हैं। वे आने वाले हफ्तों में नेवादा और जॉर्जिया में भी उपस्थित होने वाली हैं, और उन्होंने कहा है कि ‘यदि हम’ 26 पार नहीं कर पाए, तो’ 28 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।’ अमरीकी कांग्रेस के मध्यावधि चुनावों को लेकर रिपब्लिकन के रुख पर उन्होंने कहा, ‘वे बेईमानी कर रहे हैं।’ डेर्ट्रॉयट में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर केंद्रित धार्मिक नेताओं की एक सभा में उन्होंने कहा, ‘वे हमारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। हमारे पास ताकत है, और इसलिए मध्यावधि चुनाव में 42 दिन बचे होने के इस माहौल में, मैं यही कहूंगी कि हमें इतनी भारी संख्या में मतदान करना होगा कि किसी भी धांधली की गुंजाइश ही न बचे।’ पूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी अल-सईद ने अगरस की प्राइमरी में लगभग एक प्रतिशत अंक से बेहद करीबी जीत हासिल की थी, जिसमें कॉलेज-शिक्षित उदारवादियों, अरब अमरीकियों और युवा मतदाताओं का उन्हें मजबूत समर्थन मिला था। लेकिन उन्हें उम्रदराज अफ्रीकी-अमरीकी मतदाताओं को साधने में संघर्ष करना पड़ा—यह वह मतदाता वर्ग है जिसकी उन्हें नवंबर में रिपब्लिकन माइक रोजर्स को हराने के लिए सख्त जरूरत होगी। यह संयुक्त कार्यक्रम, भले ही छोटा था, लेकिन ऐसे मतदाताओं को अपने पाले में लाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। सफोक यूनिवर्सिटी के एक नए सर्वेक्षण के अनुसार, अल-सईद 47 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के साथ रोजर्स पर 7 अंकों की बढ़त बनाए हुए हैं।

सैयद कामरान

उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकारों को एक असहज सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है-मौजूदा गठबंधन में समाजवादी पार्टी (एस.पी.) की स्थिति कहीं अधिक मजबूत है। ‘इंडिया गठबंधन की एकता’ के दिखावे से परे, गणितीय समीकरण और संगठनात्मक क्षमता भी यही संकेत देती है-कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत से कहीं अधिक है।

पहला अंतर संरचनात्मक है। समाजवादी पार्टी कोई व्यक्ति-प्रधान संगठन नहीं है, जो कुछ समय के लिए जनसमर्थन बटोरकर सत्ता के पलटने पर गायब हो जाता है। इसके पास एक सक्रिय कार्यकर्ता दल और बृ्थ स्तर के कार्यकर्ता हैं, तीन दशकों में निर्मित यादव-मुस्लिम सामाजिक पूंजी है, गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) और दलितों का बढ़ता हुआ समर्थन है तथा एक जिला-से-गांव स्तर का ढांचा है जो खराब चुनावी दौर में भी टिका रहता है। इसकी तुलना तृणमूल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से करें जो ‘नेता-समर्थक’ की संरचना पर आधारित हैं, नेता की लोकप्रियता के समय ये दल शक्तिशाली होते हैं लेकिन लोकप्रियता कम होने पर इनकी संरचनात्मक मजबूती खत्म हो जाती है।

कांग्रेस का राज्य इकाई उसी खामी से ग्रस्त है, जिसका समाधान सपा ने कर लिया है। यह समर्थकों पर आधारित एक खोखली इकाई है, जो मीडिया कवरेज,



राहुल गांधी की छिटपुट यात्राओं और क्षणिक ऑनलाइन समर्थन पर निर्भर है तथा इसमें जमीनी स्तर पर ऐसी बुनियादी विपरीत, सपा का कार्यकर्ता एक स्थायी संपत्ति है, जो 2027 में चाहे कोई भी जीते, कहीं नहीं जाने वाला, यही स्थायित्व उसकी ताकत है। दूसरा तर्क, जो शायद अधिक निर्णायक है, वह है वोटों का गणित। उत्तर प्रदेश का मुकाबला अब चार-दक्षीय संघर्ष नहीं रह गया, यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सपा के नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच एक द्विध्रुवीय संघर्ष में तबदील हो गया है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का वोट शेयर लगातार घट रहा है और जो थोड़ा-बहुत वोट बचा है, साथ ही जाति आधारित और क्षेत्रीय दलों में बिखरी भाजपा विरोधी भावना, उसका कोई निश्चित टिकाना नहीं है। यह उस गैर-भाजपा गठबंधन की ओर आकर्षित होता है, जिसके जीतने की सबसे अधिक संभावना होती है।

दो ध्रुवों वाली चुनावी दौड़ में, ‘भाजपा

को छोड़कर कोई भी’ का बचा हुआ वोट समान रूप से नहीं बँटता, यह उस पार्टी के पीछे एकजुट हो जाता है, जिसे असली चुनौती देने वाली पार्टी के रूप में देखा जाता है और उत्तर प्रदेश में यह स्पष्ट रूप से सपा है, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस, जो एक दशक से अधिक समय से उत्तर प्रदेश के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में एकल अंकों में बनी हुई है, औसत विपक्षी मतदाता के लिए इस गणना का हिस्सा नहीं है। वोट बढ़ाने में इसकी क्षमता सीमित है, जबकि सपा की छवि सत्ता-विरोधी वोटों को आर्जित करती है, जो सीटों का फैसला करती है। तीसरा तर्क कथात्मक स्वामिलता का है। 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव अखिलेश यादव को विपक्ष के चेहरे के रूप में और पी.डी.ए. (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) को संगठनात्मक सामाजिक गठबंधन के रूप में उभार रहे हैं। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में पी.डी.ए. की तरह कोई प्रतिस्पर्धी कथा नहीं है, उसका राष्ट्रीय न्याय का ढांचा और भारत जोड़ो से जुड़ा संदेश पी.डी.ए. की तरह उत्तर प्रदेश की विशिष्ट कहानी के रूप में स्थानीयकृत नहीं हो पाया है।

जब एक सांझेदार का दबदबा हो और दूसरा उसमें अपनी जगह बना रहा हो, तो यह सवाल अपने आप हल हो जाता है कि ‘नेतृत्व किसके हाथ में है’। कांग्रेस के लिए एक व्यावहारिक रास्ता यह है कि वह अनुशासित सहायक सांझेदार बनकर पी.डी.ए. गठबंधन को उन सीटों पर मजबूत

करे, जहां वह लाभ पहुंचा सकती है, जैसे कि ब्राह्मण बहुल और शहरी क्षेत्र, न कि सीटों के बंटवारे में समानता पर जोर दे। अतिवादी रवैया पहले से ही नाजुक भाजपा विरोधी गठबंधन को और भी कमजोर कर सकता है।

ऐसा नहीं कि कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रतीकात्मक महत्व तो होता ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे विविधतापूर्ण राज्य में यह महत्व बराबर का प्रभाव नहीं होता। सपा के पास कार्यकर्ताओं की स्थिरता है, द्विध्रुवीय समीकरण है, जो भाजपा विरोधी बचे हुए वोटों को अपनी ओर खींचता है और यादव और सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से राजनीतिक परिदृश्य पर उसका नियंत्रण है। निष्पक्ष विश्लेषण में, यह एक ऐसा गठबंधन है, जिसमें एक सहयोगी अकेले टिक सकता है और दूसरा नहीं तथा यही असंतुलन कांग्रेस के लिए सीटों और गठबंधन में उसकी स्थिति को तय करेगा।

कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े और सीटों की मांग बढ़ा-चढ़ाकर न करे, बल्कि यथार्थवादी रखे, यानी सीमित सीटों पर ही संसाधन केंद्रित करे। कम सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने से दो फायदे होंगे-एक तो 2029 के लिए सीट बंटवारे की बातचीत में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी और दूसरा, पार्टी को मौजूदा विधायकों का एक मजबूत समूह मिलेगा। इस तरह की जमीनी उपस्थिति केंद्रीय नेतृत्व की दृश्यता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

लोकतंत्र बचाने जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा?

सनत जैन

देश इस समय एक ऐसे संवैधानिक संकट के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां सवाल केवल मतदाता सूची में नाम रहने या कटने का नहीं है। बल्कि सवाल नागरिक होने के अधिकार का है। चुनाव आयोग को लेकर देशभर में उठ रहे सवाल, एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप और अब न्याय पालिका की भूमिका पर उठती उंगलियां लोकतंत्र नागरिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के लिए बेहद गंभीर संकेत हैं। सत्य हिंदी के एक कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं चुनाव मामलों के जानकार अरुण अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश और महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिवक्ता फिरोज़ मिर्जा ने जिस तरह इन सवालों पर चर्चा की, उसने पूरे विवाद को एक नए राजनीतिक- संवैधानिक आयाम में पहुंचा दिया है। विशेष रूप से अरुण अग्रवाल द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के संबंधों तथा न्यायिक नियुक्तियों को लेकर लगाए गए आरोपों ने कई असहज प्रश्न खड़े किए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और न्यायिक जांच अलग विषय है। लेकिन लोकतंत्र में इतने गंभीर आरोपों का सामने आना भी अपने आप में चिंता का विषय है। सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस चुनाव आयोग के फैसले से करोड़ों नागरिकों के मतदान के अधिकार समाप्त कर दिए गए। उसके खिलाफ न्यायपालिका कितनी तेजी और कितनी निष्पक्षता से हस्तक्षेप कर रही है? यह चुनाव आयोग की मदद कर रही है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई और विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामलों ने यह प्रश्न पैदा किया है। कहीं प्रक्रिया इतनी जटिल तो नहीं बना दी गई कि सामान्य नागरिक अपने ही नागरिक अधिकार को साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रह जाए? मतदान केवल एक बटन दबाने की प्रक्रिया नहीं है। मतदान नागरिकता की मौलिक अधिकारों की एक राजनीतिक अभिव्यक्ति है। मतदाता सूची से नाम हटाना केवल चुनाव से बाहर होना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आवाज को खो देना है। अंग्रेजों के शासनकाल में केवल पढ़े लिखे कुछ लोगों को ही मतदान का अधिकार था। स्वतंत्रता के पश्चात बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान मतदान के अधिकार दिए गए।सत्ता में सभी की भागीदारी एक



समान रखी गई। इसलिए जब लाखों-करोड़ों नामों के हटने के आंकड़े सामने आते हैं, तो चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका तक हर संवैधानिक संस्था की जवाबदेही नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर और भी बढ़ जाती है।

यही वह बिंदु है जहां न्याय पालिका की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान ने न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान पर रखा है। विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा का अधिकार और सर्वोच्चता न्यायपालिका को संविधान ने प्रदान की है। संविधान और जनता अदालत से यह अपेक्षा नहीं करती, वह किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति के पक्ष में खड़ी हो। जनता केवल यह चाहती है कि संविधान और न्याय के पक्ष में न्यायालय निर्णय करें। यदि न्यायपालिका को लेकर यह धारणा बनने लगे, वह सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं के बीच उठ रहे विवादों में निष्पक्ष निर्णायक की भूमिका नहीं निभा रही है। तो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ ही कमजोर हो जाएगा और लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र स्थापित होने मे देर नहीं लगेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को लेकर कार्यक्रम में लगाए गए आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण तथ्य, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रिया ही कर सकती है। लेकिन आरोपों को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्यायपालिका सर्वोच्च है, इसलिए उसके खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। यदि आरोप गलत हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच हो और उसका तथ्यात्मक खंडन होना चाहिए। यदि उनमें कुछ सत्य है, तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है। जब गंभीर सवालों का जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। आज जनता के सामने मूल प्रश्न यही है।क्या

संविधान केवल किताब में सुरक्षित रहेगा या नागरिकों के जीवन में भी दिखाई देगा? यदि मतदाता सूची में नाम नहीं है, नागरिक को अपने अधिकार के लिए प्रमाणों की गठरी लेकर सरकारी कार्यालयों तथा अदालतों में बार-बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। न्याय पाने के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ेगा, नागरिक के मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे और वह हाराख पर तारीख और चक्कर पर चक्कर लगाने पर उलझा रहेगा। ऐसी स्थिति में वह अपनी रोजी-रोटी भी नहीं चल पाएगा। यहीं से विद्रोह उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का कोई अर्थ नही रह जाता है। शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रदर्शन अधिकारों के लिए होना ही चाहिए। हिंसा लोकतंत्र को मजबूत नहीं करती, बल्कि कमजोर करती है। जनता को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। सरकार और सभी संवैधानिक संस्थाओं से उनके जवाब देही को लेकर प्रश्न भी पूछने होंगे। दस्तावेज मांगने होंगे,अदालतों का दरवाजा खटखटाना होगा, अदालत नहीं सुनेगी, तो सड़कों पर आना होगा। आज लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, व्यवस्था की जवाबदेही के लिए है। 13 करोड़ नागरिकों का सवाल हो या एक नागरिक का— अधिकार संख्या देखकर तय नहीं होता। संविधान में एक नागरिक का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना तेरह करोड़ नागरिकों का है। इतनी बड़ी संख्या बगावत को जन्म देती है इसलिए अब समय आ गया है, चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका एवं सभी संवैधानिक संस्थाएं जनता को यह भरोसा दिलाए, कानून सबके लिए समान है। सभी नागरिकों के अधिकार समान है।सत्ता के लिए अलग कानून और आम नागरिक के लिए अलग कानून की धारणा लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बीमारी है। जनता यदि चुप रही, तो संस्थाएं और अधिक निरंकुश हो सकती हैं। जनता यदि संविधान हाथ में लेकर, कानून के दायरे में रहकर और शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है।तो लोकतंत्र की असली शक्ति सामने आएगी। लोकतंत्र चुनाव से शुरू होता है, लोकतंत्र की रक्षा जागरूक नागरिकों से होती है। अब सवाल यह नहीं कि जनता सड़कों पर आएगी या नहीं। सवाल यह है कि क्या संवैधानिक संस्थाएं जनता को सड़कों पर आने की नौबत आए इसके पहले ही निष्पक्षता के साथ इन सारे विवादों का निपटारा करें ताकि आम जनता का विश्वास लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर बना रहे।

एशियाई खेलों में भारत को 10 में से 8 स्वर्ण महिला खिलाड़ियों के नाम



देवेश त्रिपाठी

जापान के आइची-नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों में भारत द्वारा अब तक जीते गए दस स्वर्ण पदकों में से आठ महिला एथलीटों द्वारा जीता जाना महज पदकों की संख्या का एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय खेलों की बदलती तस्वीर और महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास का महत्वपूर्ण संकेत भी है। देश की बेटियों ने 4×400 मीटर रिले रेस, ट्रेप शूटिंग, क्रिकेट, कबड्डी, शूटिंग (मिक्स्ड टीम) और तीरंदाजी में स्वर्ण जीतकर पुरुषों पर दबाव वाले मैच हों या शूटिंग रेंज में रिकॉर्ड-तोड़ सटीकता, महिला खिलाड़ी हर बड़ी जीत का केंद्र रही हैं।

यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि भारतीय बेटियों को जब समान अवसर और सही मंच मिलता है, तो वे वैश्वक स्तर पर तिरंगा लहराकर देश का नाम रोशन करने का जज्बा रखती हैं। यही नही, बेटियों की कामयाबी समाज की उस रूढ़िवादी सोच को भी आईना दिखाती है, जो उन्हें कमजोर मानकर खेलों से दूर रखती है। मगर, ये उपलब्धियां बताती हैं कि खेलों की दुनिया में भारत को एक ‘स्पोर्टिंग नेशन’ बनाने का नेतृत्व बेटियों ने संभाल लिया है। नीरू ढांडा ने ट्रेप शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास तो रचा ही, साथ ही फाइनल मुकाबले में 30

एक और सबक कू की जांच और कॉकपिट संस्कृति का है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि विदेशी करू की स्क्रीनिंग सख्त होती है, फिर भी यह घटना हुई। चाकू या नुकलीी वस्तु कॉकपिट तक कैसे पहुंची, यह सवाल एयरलाइन और दोनों देशों की जांच एजेंसियों पर है। साथ ही यह याद दिलाता है कि दो-पायलट सिस्टम की ताकत तभी है जब दोनों एक-दूसरे पर भरोसा कर सकें। जब भरोसा टूटे, तो बचे हुए पायलट के पास कुछ ही सेकंड होते हैं। कैप्टन स्मिट ने वे सेकंड दूसरों को सौंप दिए।

भारतीय विमानन के लिए यह गर्व का क्षण है, लेकिन गर्व को ढाल न बनाया जाए। कैप्टन स्मिट की कहानी यह नहीं कहती कि भारतीय पायलट संभाव्य से हीरो होते हैं। वह कहती है कि अनुशासन, घंटों का अनुभव और संकट में प्राथमिकता तय करने की आदत जान बचाती है। इस हादसे की जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। जिससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि हथियार की उत्पत्ति, अलार्म 7500 क्यों बना और ऑफ-ड्यूटी पायलटों ने लैंडिंग कैसे संभाली? पारदर्शिता ही अगली उड़ान को सुरक्षित बनाएगी।

अंत में बात यात्री से है। अगली बार जब करू सुरक्षा कार्ड उठाए, तो उसे औपचारिकता मत समझिए। अपनी पंक्ति के एग्जिट गिनिए। यह याद रखिए कि घबराहट संक्रामक होती है और संयम भी। कल कॉकपिट में एक भारतीय पायलट ने खून बहते हुए दरवाजा खोला। केबिन में कुछ साहसी लोगों ने वह मौका व्यर्थ नहीं जाने दिया। वीरता अकेले कॉकपिट की संपत्ति नहीं रही। वह साझी हुई। यही इस घटना का सबसे जरूरी संदेश है।



बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं आउटडोर खेल

घर के बाहर जाकर खेलने के काफी फायदे हैं। तुम अपने दोस्तों के और करीब आते हो, टीमवर्क समझ आता है और तुम खूब बढ़ते हो। आउटडोर खेल ऐसे नहीं होते जिन्हें सर्दी-गर्मी के हिसाब से खेला जाए। तुम किसी भी खेल को कभी भी खेल सकते हो। बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट के अलावा कई पारंपरिक खेल भी खेल सकते हो।

ट्रेजर आइलैंड

डोरेमॉन में तुमने इसका नाम सुना होगा। वहां जाकर नोबिता और उसके दोस्त मस्ती करते हैं। लेकिन हम जिस ट्रेजर आइलैंड की बात कर रहे हैं, उसे अलग-अलग जगहों पर कई तरह के नामों से जाना जाता है। इस गेम में दो टीम बनानी होती हैं। इसमें पहली टीम किसी भी चीज को खजाना बना कर छुपा देती है। फिर पहली टीम, दूसरी टीम के लिए क्लू बनाती है। उन क्लूज को फॉलो करते हुए उस खजाने तक पहुंचना होता है। इसमें तुम टाइमिंग भी शामिल कर सकते हो। जो भी टीम खजाने को ढूँढ़ने में सफल हो जाती है, वह जीती हुई मानी जाती है।

छुपन-छुपाई

यह खेल सबसे पुराना है। तुम्हारे मम्मी-पापा ने भी इसे बचपन में जरूर खेला होगा। इसमें खूब सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं। एक बच्चे को डेन चुना जाता है। डेन चुनने के लिए तुम अक्कड़-बक्कड़ का सहारा ले सकते हो। फिर बाकी बचे सभी बच्चे अलग-अलग जगहों पर छुप जाते हैं और डेन उन्हें ढूँढ़ता है। जिस बच्चे को वह सबसे पहले ढूँढ़ लेता है, अगली बार उसे ही डेन बनना होता है। लेकिन एक को ढूँढ़ने से ही काम नहीं चलता। उसे सभी को ढूँढ़ना होता है।

अगर कोई छुपा बच्चा पीछे से जाकर उसे धप्पा कर दे तो डेन को फिर दोबारा डेन बनना होता है।

स्टापू

इस खेल में जमीन में चौकोर बॉक्सेज डिजाइन कर दिए जाते हैं। फिर इनमें एक से दस तक गिनती लिखी जाती है। हर बच्चा एक-एक करके दस खानों में स्टापू फेंकता है। लंगड़ी करते हुए उस पत्थर तक पहुंचना होता है और उसे पैर से खिसकाते हुए वापस लाना होता है। इस गेम से ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती है और हमारे पैर बेहद मजबूत होते हैं।

स्पाइंग गेम्स

ये चोर-पुलिस की तरह का गेम होता है। इसमें दो टीम होती हैं। एक टीम चोर बनती है तो दूसरी पुलिस। पुलिस वाली टीम चोर वाली टीम को खोज कर उसे कैद करती है।

क्रिकेट

इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट के पहले क्लब की स्थापना 1787 में हुई थी और पहला टेस्ट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया था। शुरुआत में क्रिकेट में टेस्ट मैच ही खेला जाता था, वनडे मैच की शुरुआत 1971 में हुई। पहला वनडे मैच भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेला गया था। तुमने आईसीसी का नाम तो जरूर सुना होगा। आईसीसी का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय मैच होते हैं, सभी की रूपरेखा आईसीसी निर्धारित करती है और वर्ल्ड कप का आयोजन करती है। अब तक क्रिकेट का वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा पांच बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, वहीं भारत दो बार विश्व विजेता बना है।



हॉकी हमारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ब्लैकहीथ एबी एंड क्लब को हॉकी का पहला संगठित क्लब माना जाता है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। हॉकी का पहला इंटरनेशनल मैच 1895 में वेल्स और इंग्लैंड के बीच खेला गया था और पहला वर्ल्ड कप 1971 में पाकिस्तान और स्पेन के बीच खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने खिताब अपने नाम किया था। जानते हो, ओलंपिक में सबसे ज्यादा आठ बार भारत ने हॉकी का मैच जीता है।



फुटबॉल

तुममें से काफी बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद होगा। जानते हो इस खेल का जन्मदाता भी इंग्लैंड ही है। भारत में अंग्रेज इस खेल को लाए और यहां के लोगों को खेलना सिखाया। फुटबॉल का पहला क्लब 1857 में स्थापित किया गया। इसका नाम शेफील्ड फुटबॉल क्लब था। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा है। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप वर्ष 1930 में उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच खेला गया था, जिसमें उरुग्वे विजेता घोषित किया गया।

टेबल टेनिस

इस खेल का जन्म भी इंग्लैंड में ही हुआ था। वर्ष 1926 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई।

जब से कंप्यूटर आया है, तब से बाहर जाकर खेलने की तो जैसे फुरसत ही नहीं मिलती तुम बच्चों को। पर क्या तुम जानते हो कि आउटडोर खेल तुम्हारे संपूर्ण विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। क्या खेलोगे, किसके साथ और कब...यह सब आज हम तुम्हें बता रहे हैं।



नीदरलैंड में है दुनिया का पहला माइक्रोब जू

नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम में दुनिया का पहला माइक्रोब जू यानी सूक्ष्म जीव 'वाटिका' खुला है। माइक्रोपिया नामक इस जीव-जंतु वाटिका को शहर के उस जंतु पार्क 'आर्टिस' में खोला गया है जिसकी स्थापना 176 साल पहले हुई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी जीव-जंतु वाटिकाओं में से एक है।

140 वर्ष पुरानी इमारत में रखा एक खूबसूरत भूरे रंग का बक्सा बैवटीरिया, फंगस, कई तथा अन्य एक कोशिका वाले जीवों का आवास है। ये वे जीव हैं जिन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता परंतु धरती पर जीवन इनसे ही संभव है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि सूक्ष्म जीवों में से केवल 1 प्रतिशत के बारे में ही आज तक इंसान जान सका है। कई लोगों के लिए सूक्ष्म जीव नफरत व भय की भावनाएं पैदा करते हैं। दरअसल, यह डर उस चीज से है जिसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है और लोगों के मन से सूक्ष्म जीवों के बारे में इसी डर को दूर करना इस जीव-जंतु वाटिका का पहला मकसद है। हेग कहते हैं कि यदि हम प्रकृति को जानना चाहते हैं तो हमें सूक्ष्म जीवों को भी जानना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान इन सूक्ष्म जीवों से बेशक नफरत करता हो लेकिन हर

इंसान का शरीर अरबों सूक्ष्म जीवों का घर होता है। केवल इंसानों की एडी में ही 80 प्रकार के अलग-अलग सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इस बात की पुष्टि के लिए यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने शरीर का बॉडी स्कैन करवा कर देख सकता है।

चाहें तो यहां एक अन्य दिलचस्प तरीका भी है। एक जगह फर्श पर लाल रंग का दिल बना है। जैसे ही यहां खड़े होकर कोई जोड़ा एक-दूसरे का चुम्बन लेता है, करीब लगे 'किस' मीटर की स्क्रीन पर नम्बर बढ़ते जाते हैं, जब तक कि मीटर में से संदेश न आने लगे कि 'आप दोनों ने अभी 10 लाख सूक्ष्म जीवों का

आदान-प्रदान किया है।' माइक्रोपिया में दिखाया जाता है कि सूक्ष्म जीव कैसे जीते हैं, कैसे भोजन करते हैं और कैसे प्रजनन करते हैं? बैवटीरिया इतने छोटे होते हैं कि एक सूई की नोक पर 10 लाख बैवटीरिया आराम से समा सकते हैं। उच्च विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञानी इन धारणाओं पर 12 साल से अधिक वक्त से माथापच्ची कर रहे हैं।

यहां उन सूक्ष्म जीवों को प्रदर्शित किया गया है जो कृत्रिम वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले एड्स वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों को केवल मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया गया है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए यहां माइक्रोस्कोप के लेंस के साथ जोड़ा गया एक थ्री डी टैलीस्कोप है, जो नंगी आंखों से न दिखने वाले सूक्ष्म जीवों को हजार गुणा बड़ा करके दिखाता है।

इनका रखो ध्यान



- आउटडोर गेम्स के साथ इतनी सारी अच्छी बातें जुड़ी हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन बातों का ख्याल रखने पर ही आउटडोर गेम्स खेल कर भी तुम पढ़ाई को और परिवार को पूरा टाइम दे सकते हो।
- सबसे पहले तो खेलने के लिए ऐसी जगह चुनो, जो घर के आसपास हो, यानी जहां से घर वाले तुम्हें आवाज देकर बुला सकें। अगर आसपास खेलने की जगह नहीं है तो अपने पड़ोस के दोस्तों के साथ करीब की किसी जगह पर खेलने जा सकते हो, लेकिन रोज नहीं। और इस जगह के बारे में घर वालों को पता भी होना चाहिए।
- ऐसे दोस्तों के साथ खेलना शुरू करो, जिन्हें तुम पहचानते हो या जो तुम्हारे ही जैसे हों। बाहर खेलने का यह मतलब नहीं है कि तुम इनडोर गेम्स को पूरी तरह गुड़बाय कह दो, क्योंकि एक तो इनसे भी तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है, दूसरे आउटडोर गेम्स रोज नहीं खेले जा सकते।
- ज्यादातर ऐसे गेम्स के लिए टीम की जरूरत पड़ती है और कभी-कभी दोस्तों का बाहर आकर खेलने का मन नहीं होता। अगर इन सारी बातों का ध्यान रखोगे तो तुम्हें आउटडोर गेम्स के बहाने एक नई दुनिया देखने को मिलेगी। नए दोस्त बनेंगे, फिजिकल फिटनेस रहेगी और कई सारी नई बातें भी सीख सकोगे। तो फिर देर किस बात की है, तुम अपने आसपास के दोस्तों के साथ मिल कर गेम प्लान करो और खेलने के लिए तैयार हो जाओ।



बनी कैसे ऊन?

दोस्तों, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जिस ऊन का स्वेटर पहन हम सर्दी से बचते हैं, वह बनी कैसे? जरूर वो इंसान बहुत ही बुद्धिमान होगा, जिसने भेड़ को देखकर उससे ऊन बनाने के प्रयोग करने के बारे में सोचा होगा। यह माना जाता है कि बुनने के लिए ऊन का ही सर्वप्रथम उपयोग प्रारंभ हुआ। ऊनी वस्त्रों के टुकड़े मिस्र बैबिलोन की कब्रों, पुरातन ब्रिटेन निवासियों के झोपड़ों के साथ मिले हैं। रोमन आक्रमण से पहले भी ब्रिटेन वासी इनका उपयोग करते थे। विचेस्टर फैक्टरी ने ऊन का तरह-तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके बाद इसका इंग्लैंड में खूब प्रयोग किया जाने लगा। हेनरी द्वितीय ने कानून, वस्त्रहाट और बुनकारी संघ बनाकर इस उद्योग को प्रोत्साहित किया। सन् 1788 में हाटफोर्ड (अमेरिका) में जल-शक्ति-चालित ऊन फैक्टरी आरंभ हुई। ऊन सफेद, काले और भूरे रंग में ही मिलती है। पालतू भेड़ों की ऊन सफेद रंग की होती है। रंगीन ऊन सबसे अधिक पुरानी नस्ल की उन भेड़ों से मिली है, जो कालीन बुनने लायक मोटे किस्म की ऊन पैदा करती हैं।



प्रधानमंत्री मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छर से की बात

नई दिल्ली।



फ्लाइटडुबई की एफजेड1073 फ्लाइट में कॉकपिट के अंदर हुए हमले में घायल भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर से प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को फोन पर बात की। बातचीत के दौरान कैप्टन स्मित ने प्रधानमंत्री को उस खौफनाक घटना के बारे में बताया और यह भी साझा किया कि मुश्किल हालात में उन्हें हिम्मत कहाँ से मिली। करीब नौ मिनट चली वीडियो कॉल में पीएम मोदी और स्मित ने कठिन परिस्थिति में हौसला बनाए रखने, संस्कार और साहस से जुड़े पहलुओं पर बातचीत की। कैप्टन स्मित फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात में इलाज करा रहे हैं। पीएम मोदी ने बातचीत में उनकी बहादुरी की सराहना की और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित के साहस को लेकर सार्वजनिक रूप से उनकी तारीफ की थी। पीएम मोदी से बातचीत के दौरान कैप्टन स्मित भावुक हो गए। कैप्टन स्मित ने पीएम मोदी को बताया कि जब भी वह मुश्किल में होते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं।

संसद भवन में महात्मा गांधी-शारूजी को दी गई श्रद्धांजलि

नई दिल्ली।



सदन के केंद्रीय कक्ष में शुक्रवार को राष्ट्रपति महात्मा गांधी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई सांसद और मंत्रियों ने देश के महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया था। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बच्चे प्रधानमंत्री से मिलकर बेहद खुश और उत्साहित दिखाई दिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बच्चों से बात करते नजर आए। महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज लाल बहादुर शास्त्री की भी 122वीं जयंती है।

चुनाव आयोग पर झूठ नहीं चलेगा : देवेन्द्र फडणवीस

मुंबई।



जब कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ और एसआईआर प्रोसेस में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ फैलाई जा रही झूठी बातें चुनाव आयुक्त के प्रेस बयान के बाद बेबुनियाद साबित हो गई हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, पूरा मामला सामने आ गया है। तीनों चुनाव आयुक्तों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उनकी झूठी बातें बेबुनियाद साबित हो गई हैं। फिर भी, इस झूठी बात को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। वे इसमें सफल नहीं होंगे। फडणवीस मुंबई में शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और दूसरे सिविल सोसाइटी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव आयोग और स्पेशल इंटेसिव रिविज्न् (एसआईआर) प्रोसेस में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ किए जा रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच बोल रहे थे।

राज्यसभा चुनाव में सपा उतारेगी तीसरा उम्मीदवार

चंदौली (उप्र)।



समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद वीरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए तीसरा उम्मीदवार उतारेगी। सपा के इस ऐलान से 10 सीट के लिए होने वाले चुनाव में मुकाबले की स्थिति बन गई है। चंदौली के सांसद ने दिल्ली से फोन पर 'मीडिया' से बातचीत में कहा कि तीसरे उम्मीदवार के नाम का फैसला शुक्रवार को किया जाएगा और पांच अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार इन चुनाव के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अक्टूबर है। सपा ने 30 सितंबर को पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव और रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के अध्यक्ष धनराज परमिल नाथवानी को चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया था। बाद में दोनों ने लखनऊ में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।

राजा वड़िंग ने औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा राहुल को सौंपा

नईदिल्ली।



पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित 10 जनपथ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से करीब एक घंटे तक मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद हुई इस मुलाकात को पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व बदलाव के बीच अहम माना जा रहा है। वड़िंग ने मुलाकात के बाद बताया कि उन्होंने राहुल गांधी को औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वड़िंग ने कहा कि राहुल गांधी के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात, सरकार की स्थिति और आगे पार्टी को किस तरह काम करना चाहिए, इस बारे में जानकारी ली। वड़िंग के मुताबिक, उन्होंने राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर अपने करीब साढ़े चार साल के अनुभव को साझा किया। उन्होंने पंजाब में कांग्रेस के सामने मौजूद चुनौतियों, उनसे निपटने के तरीकों और पार्टी की ताकत के बारे में राहुल गांधी से विस्तार से चर्चा की।

अखिल भारतीय विहार सेवा समूह के सम्मेलन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले

धर्म और राष्ट्र एक-दूसरे के पूरक, संकट में दुनिया को भारत से राह की उम्मीद

मुंबई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि भारत में धर्म और राष्ट्र अलग-अलग नहीं हैं तथा दुनिया के सामने मौजूद कई चुनौतियों से निपटने में देश की विशाल ज्ञान-परंपरा की भूमिका रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख ने अखिल भारतीय विहार सेवा समूह के 14वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया विकास और पर्यावरण संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक जीवन, तथा धार्मिक आस्था और संघर्ष के बीच विरोधाभासों से जूझ रही है। उन्होंने कहा, जैसे-जैसे विकास बढ़ता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है।

वहीं, जहां पर्यावरण की रक्षा करनी होती है, वहां विकास नहीं हो पाता। जैसे-जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ती है, परिवार बिखर रहे हैं। समाज में भी विघटन हो रहा है। भागवत ने कहा कि भारत की ऐतिहासिक परंपरा रही है कि वह दूसरे देशों पर विजय हासिल किए बिना या लोगों का धर्मांतरण किए बगैर अपना ज्ञान साझा करता रहा है।

उन्होंने कहा, दुनिया जानती है कि रास्ता भारत से निकलेगा। उन्होंने कहा कि भारत के पास एक विशाल ज्ञान परंपरा है जिसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, जैन आगम, त्रिपिटक, गुरु ग्रंथ साहिब और सतों की शिक्षाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा, हमारे देश के पास ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना है, जिसकी आज दुनिया



को जरूरत है। भागवत के अनुसार, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले लोगों के जीवन और परंपराओं की रक्षा करना केवल एक धार्मिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि मानवता की सेवा है।

भागवत ने यहां कहा, हमारा राष्ट्र और धर्म अलग नहीं हैं। राष्ट्र का उद्देश्य धर्म है और धर्म राष्ट्र को बनाए रखने में मदद करता है। दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

अगर एक है तो दूसरा भी है और अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्र कमजोर होता है तो धर्म भी खतरे में पड़ जाता है। भागवत ने कहा, अगर धर्म का पालन कमजोर पड़ता है, तो दोनों को साथ-साथ सही तरीके से आगे बढ़ाना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय दृष्टिकोण केवल किसी एक वर्ग के कल्याण तक सीमित नहीं है।

भागवत ने कहा, हमारे पूर्वजों ने पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचा। हम कहते हैं कि सभी सुखी रहें। हम यह नहीं मानते कि कुछ लोग समृद्ध हों

और कुछ नहीं।

यहां ऐसा कोई दोहरा मापदंड नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग लगातार पीड़ित रहते हैं तो अधिक से अधिक लोगों का अधिकतम कल्याण का विचार भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा, भले ही अधिकतम

संख्या में लोग खुश हों लेकिन अगर कुछ लोग भी पीड़ित हैं, तो उनका दुख सभी की खुशी को नष्ट कर देता है। भागवत ने यह भी कहा कि दुनिया में मौजूद संघर्षों और दुविधाओं का समाधान किसी एक पक्ष को दूसरे की कीमत पर चुनकर नहीं किया जा सकता। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक जीवन के बीच के तनाव को जिक्र करते हुए कहा, अगर समूह को एकजुट रखना है, तो ऐसा लगता है कि

व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबाना होगा। उन्होंने कहा, अगर धार्मिक आस्था बढ़ती है तो यह पता नहीं कि आस्था कितनी बढ़ती है, लेकिन कट्टरता जरूर बढ़ती है। इससे लोगों के बीच संघर्ष पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने करीब 3,000 वर्षों से किसी देश को जीते बिना, किसी का धर्मांतरण किए बिना और किसी पर हमला किए बिना सुख और शांति का मार्ग दिखाया है।

आरएसएस प्रमुख ने कहा, इसलिए लोगों को हमसे उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण समर्पण में असाधारण शक्ति होती है।

भागवत ने कहा, हमारा राष्ट्र और धर्म अलग नहीं हैं। राष्ट्र का उद्देश्य धर्म है और धर्म राष्ट्र को बनाए रखने में मदद करता है। दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्र कमजोर होता है तो धर्म भी खतरे में पड़ जाता है। भागवत ने कहा, अगर धर्म का पालन कमजोर पड़ता है, तो दोनों को साथ-साथ सही तरीके से आगे बढ़ाना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय दृष्टिकोण केवल किसी एक वर्ग के कल्याण तक सीमित नहीं है।

भागवत ने कहा, हमारे पूर्वजों ने पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचा। हम कहते हैं कि सभी सुखी रहें। हम यह नहीं मानते कि कुछ लोग समृद्ध हों

और कुछ नहीं। यहाँ ऐसा कोई दोहरा मापदंड नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग लगातार पीड़ित रहते हैं तो अधिक से अधिक लोगों का अधिकतम कल्याण का विचार भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा, भले ही अधिकतम

संख्या में लोग खुश हों लेकिन अगर कुछ लोग भी पीड़ित हैं, तो उनका दुख सभी की खुशी को नष्ट कर देता है। भागवत ने यह भी कहा कि दुनिया में मौजूद संघर्षों और दुविधाओं का समाधान किसी एक पक्ष को दूसरे की कीमत पर चुनकर नहीं किया जा सकता। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक जीवन के बीच के तनाव को जिक्र करते हुए कहा, अगर समूह को एकजुट रखना है, तो ऐसा लगता है कि

व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबाना होगा। उन्होंने कहा, अगर धार्मिक आस्था बढ़ती है तो यह पता नहीं कि आस्था कितनी बढ़ती है, लेकिन कट्टरता जरूर बढ़ती है। इससे लोगों के बीच संघर्ष पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने करीब 3,000 वर्षों से किसी देश को जीते बिना, किसी का धर्मांतरण किए बिना और किसी पर हमला किए बिना सुख और शांति का मार्ग दिखाया है।

आरएसएस प्रमुख ने कहा, इसलिए लोगों को हमसे उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण समर्पण में असाधारण शक्ति होती है।

भागवत ने कहा, हमारा राष्ट्र और धर्म अलग नहीं हैं। राष्ट्र का उद्देश्य धर्म है और धर्म राष्ट्र को बनाए रखने में मदद करता है। दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्र कमजोर होता है तो धर्म भी खतरे में पड़ जाता है। भागवत ने कहा, अगर धर्म का पालन कमजोर पड़ता है, तो दोनों को साथ-साथ सही तरीके से आगे बढ़ाना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय दृष्टिकोण केवल किसी एक वर्ग के कल्याण तक सीमित नहीं है।

भागवत ने कहा, हमारे पूर्वजों ने पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचा। हम कहते हैं कि सभी सुखी रहें। हम यह नहीं मानते कि कुछ लोग समृद्ध हों

लखनऊ। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक पार्टियां अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिशें बढ़ा रही हैं। हालांकि इंडिया ब्लाक और एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन गठबंधन के सहयोगी दल ज्यादा सीटें पाने के लिए दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन सूर्य के मुताबिक, समाजवादी पार्टी (सपा) कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है और इसके बजाय पार्टियों के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें बहुत कम सीटें देने पर विचार कर रही है।

सूर्य के मुताबिक, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ सीट-शेयरिंग का फॉर्मूला तय करते समय चुनावी प्रदर्शन पर ध्यान दे रही है। सपा गठबंधन। तहत कांग्रेस को लगभग 53 से 55 सीटें देने का प्रस्ताव दे रही है, जबकि पार्टी खुद लगभग 350 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। खबरों के अनुसार, समाजवादी पार्टी का यह रुख इस बात के आकलन पर आधारित है कि किन सीटों पर उसकी स्थिति सबसे मजबूत है। सूर्य ने बताया कि पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां उसकी चुनावी प्रतियोगिता मजबूत है। प्रस्तावित फॉर्मूले में 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों को भी ध्यान में रखा गया है। कांग्रेस ने 2024 के चुनावों में उत्तर



प्रदेश में छह लोकसभा सीटें जीती थीं। इन सीटों के अंतर्गत 30 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जबकि 11 विधानसभा सीटें उन लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं जहां कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गई थी। सूर्य के अनुसार, सपा कांग्रेस के लिए 53 से 55 सीटों का प्रस्तावित आंकड़ा तय करने के लिए इन क्षेत्रों में कांग्रेस के विधानसभा-वार प्रदर्शन को अपने हिसाब-किताब का आधार बना रही है। इसी तरह, समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन का भी आकलन कर रही है, जिसमें जीती गई 37 सीटें और वे क्षेत्र शामिल हैं जहां वह हार गई थी लेकिन विधानसभा स्तर पर उसे बढ़त मिली थी। सूर्य ने बताया कि इसी आकलन के आधार पर पार्टी लगभग 350 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

कांग्रेस नेताओं ने कई बार संकेत दिया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र

पाल गौतम और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने कई मौकों पर पार्टी की इस मांग के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की है। सूर्य का कहना है कि सीट बंटवारे को लेकर चला

रही बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता समाजवादी पार्टी पर दबाव भी बना रहे हैं। हालांकि, सूर्य के मुताबिक, सपा दबाव में आकर अपने प्रस्तावित फॉर्मूले में कोई बड़ा बदलाव करने को तैयार नहीं दिख रही है।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव से पहले गठबंधन किया था, जिसमें दोनों पार्टियां 298:105 के सीट-बंटवारे फॉर्मूले पर सहमत हुई थीं। इस व्यवस्था के तहत, सपा को राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 298 सीटों पर चुनाव लड़ना था, जबकि कांग्रेस को 105 सीटें दी गई थीं। हालांकि, इस फॉर्मूले को लागू करने में कुछ दिक्कतें आईं और आखिरकार दोनों पार्टियों ने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में अपने-अपने उम्मीदवार उतार दिए। चुनाव में सपा ने कुल 311 सीटों पर और कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा। सपा ने 47 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस सूर्य 2017 में केवल सात सीटों पर ही सिमट गई।

स्टेल

प्रमुख समाचार

लवलीना ने भारत को दिलाया महिला मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक

आइची नागोया।



ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरोगोहेन ने शुक्रवार को यहां चीन की बाओ जियी को हराकर भारत के लिए एशियाई खेलों की महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। लवलीना ने 75 किग्रा वर्ग के फाइनल में बाओ को 5-0 के

सर्वसम्मत फैसले से मात दी।

इस जीत के साथ उन्होंने पिछले एशियाई खेलों में जीते रजत पदक का रंग बदलकर स्वर्ण कर लिया। पिछली बार उन्हें फाइनल में चीन की एक अन्य मुक्केबाज ली कियान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

लवलीना एशियाई खेलों में मुक्केबाजी का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। उनसे पहले महान मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में 51 किग्रा फ्लाइटवेट वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था। आइची-नागोया में भारतीय मुक्केबाजों ने पिछले एशियाई खेलों के प्रदर्शन में सुधार करते हुए अब तक छह पदक पकड़े कर लिए हैं। प्रिया घंधास (60 किग्रा), कपिल पोखरिया (90 किग्रा) और नरेंद्र बरवाल (90 किग्रा से अधिक) ने कांस्य पदक जीते हैं। परवीन हुड्डा (65 किग्रा) और अंकुश पंधाल (80 किग्रा) दिन में बाद में स्वर्ण पदक के लिए रिंग में उतरे।

एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजी प्रदर्शन 2010 के ग्वांगझोउ खेलों में रहा था, जहां भारतीय दल ने कुल नौ पदक जीते थे। इनमें दो स्वर्ण, तीन रजत और चार कांस्य पदक शामिल थे। महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाजों का यह शानदार प्रदर्शन पिछले महीने र्लासो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रिकॉर्डतोड़ अभियान के बाद आया है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

भारत में संरचनात्मक रूप से जरूरत से अधिक विनिर्माण क्षमता नहीं

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जी20 अध्यक्षता द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में भारत में संरचनात्मक रूप से जरूरत से अधिक विनिर्माण क्षमता नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक, दोनों जरूरतों को पूरा करती है। वर्ष 2026 में जी20 की अध्यक्षता अमेरिका कर रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि औद्योगिक क्षमता अपने आप में कोई समस्या नहीं है। हालांकि, अगर उत्पादन भौगोलिक रूप से कुछ क्षेत्रों में छिपी हुई सब्सिडी और सहायता के कारण केंद्रित होता है, तो इससे विकृतियां पैदा हो सकती हैं। मंत्री ने कहा कि उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना एक वैध उद्देश्य है लेकिन इसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों से बाहर के उपायों या विकासशील देशों पर समायोजन का बोझ डालने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

शॉपिंग मॉल में खुदरा स्थानों की पट्टा मांग 38 प्रतिशत घटी

नई दिल्ली। देश के आठ प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर में शॉपिंग मॉल में खुदरा स्थानों की पट्टा मांग 38 प्रतिशत घटकर 7.1 लाख वर्ग फुट रह गई। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार, 2026 की तीसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में हाई-स्ट्रीट (मुख्य बाजारों) पर खुदरा स्थलों की पट्टा मांग 33 प्रतिशत बढ़कर 15.1 लाख वर्ग फुट हो गई। इन आठ शहरों में मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद शामिल हैं। शॉपिंग मॉल और हाई-स्ट्रीट को मिलाकर कुल खुदरा स्थलों की पट्टा मांग जुलाई-सितंबर तिमाही में करीब पांच प्रतिशत घटकर 22.2 लाख वर्ग फुट रह गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 23.3 लाख वर्ग फुट थी। जुलाई-सितंबर में खुदरा स्थल की पट्टा मांग में हाई-स्ट्रीट स्थानों का दबदबा रहा।

जून तिमाही में शहरी परिवारों ने एफएमसीजी खर्च घटाया: रिपोर्ट

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले एफएमसीजी उत्पादों पर शहरी परिवारों के खर्च में कमी आई। ईंधन और खाद्य वस्तुओं की कीमतों से जुड़ी चिंता के बीच लोगों ने गैर-जरूरी चीजों की खरीदारी कम कर दी। वर्ल्डपैनल (पूर्व में कंटार) की चौथी वार्षिक खर्चा रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल-जून तिमाही में शहरी परिवारों का तिमाही खर्च सालाना आधार पर चार प्रतिशत घट गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में इसमें 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि समृद्ध और कम समृद्ध शहरी परिवारों के खर्च में चार प्रतिशत की कमी आई। समृद्ध शहरी परिवारों का औसत तिमाही खर्च 81,759 रुपए रहा जबकि कम समृद्ध शहरी परिवारों का खर्च 49,832 रुपए रहा। इसके विपरीत, ग्रामीण परिवारों का खर्च 15 प्रतिशत बढ़कर 53,760 रुपए प्रति तिमाही हो गया।

चार कंपनियों को आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी

नई दिल्ली। डेनमार्क की शराब कंपनी कार्ल्सबर्ग ग्रुप की भारतीय इकाई कार्ल्सबर्ग इंडिया लिमिटेड, टीएमसी ट्रांसफॉर्मर्स (इंडिया) लिमिटेड, उजिन फार्मा लिमिटेड और मातंगी रबड़ लिमिटेड की प्रस्तावित आर्थिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) को इन चारों कंपनियों के आईपीओ दस्तावेज मई से जुलाई के बीच मिले थे। नियामक ने 28 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच उनके आईपीओ प्रस्तावों की समीक्षा पूरी की। सेबी की वेबसाइट से यह जानकारी मिली है। सेबी की मंजूरी मिलने के बाद कंपनियां लागू नियामकीय आवश्यकताओं के अधीन अपने सार्वजनिक निर्गम की तैयारियां आगे बढ़ा सकती हैं।

निजी निवेश बढ़ाना है तो क्या बदलना होगा गारंटी कोष में?

विनायक चटर्जी

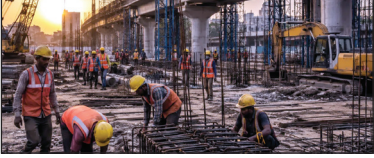
राजकोषीय अनुदान किसी भी परियोजना की प्रारंभिक लागत को कम करते हैं। व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के जरिये परियोजना व्यय के 40 प्रतिशत तक बगैर किसी लागत के वित्त मुहैया कराया जाता है (मुख्य रूप से हाइब्रिड वार्षिकी परियोजनाओं के लिए बोली मानदंड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है), जबकि धारा 80-आईए (बुनियादी ढांचे के लिए 10 साल की कर छूट) और कर-मुक्त बॉन्ड निवेश की कई राशि लौटाने को आसान बनाते हैं। सरकारी सहायता के कई अन्य रूप भी हैं।

केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित अवसरंचना जोखिम गारंटी कोष (आईआरजीएफ) का उद्देश्य था, 'बुनियादी ढांचे के विकास और निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान जोखिमों के संबंध में निजी डेवलपर्स के विश्वास को मजबूत करना और

उधारदाताओं को विवेकपूर्ण ढंग से निर्धारित आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करना'।

आईआरजीएफ को अब लगभग 1,000 करोड़ रुपये के सरकारी सहायता प्राप्त कोष के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी के तहत एक ट्रस्ट के रूप में किया जाता है। निर्माणधीन परियोजनाओं के लिए इस सुविधा का लाभ उठाने के वास्ते पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं-

- यह एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) या प्राइवेट फंडिंग वाली बुनियादी ढांचा परियोजना होना चाहिए, जिसमें सरकारी या अर्द्ध-सरकारी पक्षकारों के साथ रियायती समझौते हों।
- यह गारंटी केवल उस विलंब पर लागू होती है जो डेवलपर के नियंत्रण से बाहर होता है। इसे आमतौर पर 'सॉवरिन जोखिम' कहा जाता है, जैसे भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण



संबंधी मंजूरी आदि। अप्रत्याशित घटनाएं भी इसमें शामिल हैं।

3. परियोजना की लागत 200 करोड़ रुपये से 5,000 करोड़ रुपये के बीच होनी चाहिए।

गणना के प्रयोजनों के लिए, ऋण-इक्रिटी अनुपात 75%25 पर और लागत वृद्धि, मूल परियोजना लागत के 30 फीसदी पर सीमित की गई है, जबकि भुगतान की गणना उस स्वीकृत वृद्धि के केवल ऋण वाले भाग पर की जाती है, जिसे उसी ऋण-इक्रिटी अनुपात पर वित्त पोषित किया जाता है। उदाहरण के लिए, लगभग 5,000 करोड़ रुपये की परियोजना में अगर 10 फीसदी यानी लगभग

500 करोड़ रुपये की लागत वृद्धि होती है, तो अधिकतम भुगतान लगभग 375 करोड़ रुपये का होगा।आईआरजीएफ योजना के व्यापक मूल्यांकन से छह आयाम सामने आते हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आईआरजीएफ गारंटी सरकारी कारणों से जुड़ी देरी के साथ-साथ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण होने वाली लागत वृद्धि को वहन करती है। चूंकि 'कवर किए गए खतरे' की एक विस्तृत सूची तैयार करना लगभग असंभव है, इसलिए उस एक स्पष्ट उपबंध से मदद मिलेगी जो मंजूरी समिति को अपने विवेकाधिकार से नियंत्रित लेने की अनुमति दे।

एक 400 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले सुव्यवस्थित राजमार्ग की लागत लगभग 6,000 करोड़ रुपये होगी (भूमि अधिग्रहण को छोड़कर)। इसी प्रकार, एक 1,200 मेगावॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र की लागत भी

लगभग 8,000 करोड़ रुपये होगी। इस प्रकार, परियोजना लागत की 5,000 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित करने से आईआरजीएफ का दायरा काफी कम हो जाता है।

भारत का वार्षिक अवसरंचना व्यय लगभग 25 लाख करोड़ रुपये और निजी पूंजी की भागीदारी लगभग 20 फीसदी है, जो लगभग 5 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। पांच साल की परियोजनाओं में यह लगभग 25 लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश है। यदि 10 फीसदी परियोजनाओं में भी समय या लागत में वृद्धि होती है, तो कुल परियोजना लागत में वृद्धि (अधिकतम 30 फीसदी) लगभग 75,000 करोड़ रुपये होगी, और इस वृद्धि की लागत के लिए ऋण जोखिम (अधिकतम 75 फीसदी) लगभग 56,250 करोड़ रुपये होगा। इसके मुकाबले, लगभग 1,000 करोड़ रुपये का कोष स्वागत योग्य लेकिन अपायित शुरुआत हो सकता है।

महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर डॉ. अंबेडकर को किया नमन

नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ राज्यपाल डेका ने की पदयात्रा



रायपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आज राजधानी रायपुर में सेवा संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ पदयात्रा आयोजित की गई। राज्यपाल श्री रमन डेका पदयात्रा में शामिल हुए और नागरिकों को नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया।

राज्यपाल श्री डेका ने टाउन हॉल परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की



प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने टाउन हॉल से शुरू हुई पदयात्रा में सहभागिता की। पदयात्रा के दौरान भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया।

टाउन हॉल से प्रारंभ होकर पदयात्रा अंबेडकर चौक पहुंची, जहां राज्यपाल श्री डेका ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें

श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए सामूहिक सहभागिता और जनजागरूकता को महत्वपूर्ण बताया।

पदयात्रा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायकपुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी सहित बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, विद्यार्थी और शहर के नागरिक शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया।

राज्यपाल डेका ने गांधी जयंती पर की साफ-सफाई

राज्यपालमन डेका ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोक भवन परिसर के बाहर में साफ-सफाई क र स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने लोक भवन परिसर में स्वच्छता गतिविधियों में सहभागिता करते हुए स्वयं साफ-सफाई की। लोक भवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी सुबह परिसर के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने झाड़ू लगाकर कचरे को एकत्रित किया तथा उसका उचित निपटान किया। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि इसे हमें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। स्वच्छ और सुंदर परिसर के साथ स्वच्छ समाज के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की



सत्य, अहिंसा व सादगी के आदर्श हमें राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देते रहेंगे : साय



मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री

विष्णुदेव साय ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और मानवता के मार्ग पर चलते हुए पूरी दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश दिया। उनके विचारों में समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण और आत्मनिर्भर भारत की भावना निहित थी। उनका जीवन हमें सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर

शास्त्री का स्मरण करते हुए कहा कि उनका सादगीपूर्ण जीवन, दृढ़ नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत है। उनका दिया 'जय जवान-जय किसान' का मंत्र देश की सुरक्षा और समृद्धि में हमारे जवानों तथा किसानों के अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन एवं आदर्श हमें जनकल्याण, सुशासन और राष्ट्रसेवा के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

बस्तर बाढ़ से तबाह, सरकारी मदद केवल खानापूर्ति : दीपक बैज

रायपुर। लगभग पूरा बस्तर संभाग लगातार दूसरे वर्ष भी भीषण बाढ़ की चपेट में आया है। इस वर्ष भी बाढ़ ने आम आदमी को बर्बाद कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोगों के मकान, सामान, पशुधन, फसल सब बर्बाद हो गये। अनेकों मार्ग का संपर्क टूट गया, पुल-पुलिये, सड़क सभी कुछ टूट कर बर्बाद हो गया है। जन-जीवन ढप हो गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दुर्भाग्यजनक है कि मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों



का दौरा करने बस्तर आये लेकिन वे केवल औपचारिकता निभाकर पुल पर खड़े होकर 'फोटो खिंचवाकर, रील बनवाकर चले गये। मुख्यमंत्री का दौरा बेहद ही संवेदनहीन रहा। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से हुए नुकसान और परेशानों को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री नहीं कोई पर्यटक आया था जो फोटो खिंचवाया और चला गया। यहां से जाने के

बाद उन्हें सिंगापूर जाने की जल्दी थी। वे इन्वेस्टर कनेक्ट के बहाने सिंगापूर घूमने की तैयारी करने चले गये। बस्तर का आम आदमी परेशान है, न मुख्यमंत्री को फ्रिक है और न ही मंत्रियों को। बाढ़ से आठ लोगों की मौत हुई, उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने कोई विशेष सहायता की घोषणा नहीं किया। उड़ीसा के द्वारा बांध से पानी छोड़ने से बाढ़ के हालात बिगड़े, मुख्यमंत्री दिल्ली में उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ बैठक किये, इस पर आपत्ति क्यों नहीं व्यक्त किये।

9 माह में 1270 रु. कामर्शियल गैस के दाम बढ़े : कांग्रेस

रायपुर। पिछले 9 माह में कामर्शियल सिलेंडर के दाम में 1270 रु. की बढ़ोतरी मोदी सरकार ने किया है। मतलब हर माह 141 रु. दाम बढ़ाया गया है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि कामर्शियल गैस के दामों में बढ़ोतरी मोदी सरकार का जनता पर महंगाई और बोझ है। मोदी सरकार ने



कामर्शियल सिलेंडर के दामों में 62.50 रु. से लेकर 71.50 रु. तक महंगा कर दिया। कामर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से बाजार में मिलने वाली खाद्य सामग्री, रेस्टोरेंट, होटलों में मिलने वाले कुक फुड नाश्ता, भोजन आदि के दाम स्वाभाविक रूप से और बढ़ जायेंगे। कामर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से इंडस्ट्रियल उत्पादों के दाम भी बढ़ जायेंगे।

3 स्कूल, 500 बच्चे और मुफ्त पोषण सहयोग

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए गुरुवार को साईंशयोर न्यूट्रिशन कार्यक्रम के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की।

श्री सत्य साईं अन्नपूर्णा ट्रस्ट के सहयोग से शुरू हुए इस कार्यक्रम के पहले चरण में रायपुर जिले के 3 शासकीय विद्यालयों के करीब 500 बच्चों को मुफ्त पोषण सहयोग दिया जाएगा।

पायलट प्रोजेक्ट के तहत नवीन प्राथमिक शाला धनागांव, प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल परसदा और शासकीय विद्यालय छेरीखेड़ी के बच्चों को साईंशयोर न्यूट्रिशन उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को नियमित पीछिक आहार सहयोग देना है।



इससे उनके स्वास्थ्य, एकाग्रता, सीखने की क्षमता और समग्र विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर श्री सत्य साईं अन्नपूर्णा ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आनंद कडली, शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्कूलों के शिक्षक, श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल की टीम और अन्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने बच्चों को साईंशयोर न्यूट्रिशन

का वितरण कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की।

25 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच रही सेवा

ट्रस्ट के अनुसार, वर्तमान में देश के 25 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में एक करोड़ से अधिक स्कूली बच्चों तक प्रातःकालीन पोषण सेवा पहुंचाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम की शुरुआत के पीछे जुलाई 2026 में हुई एक मुलाकात भी अहम रही। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सत्य साईं ग्राम, मुद्देनहल्ली का दौरा कर सद्गुरु मधुचूदन साईं से भेंट की थी। इस दौरान पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई थी।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

रिफॉर्म उत्सव एवं राजभाषा हिंदी पखवाड़ा आयोजित

रायपुर। भा.कू.अनु.प -राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, रायपुर में रिफॉर्म उत्सव एवं राजभाषा हिंदी पखवाड़ा-2026 के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का समापन समारोह उत्सवह पूर्वक आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों, वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता की। कार्यक्रम में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर प्रो. राजेश दुबे ने मुख्य वक्ता के रूप में सहभागिता की। उन्होंने राजभाषा हिंदी की महत्ता, कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रभावी प्रयोग तथा हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन की दिशा में किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं तथा ऐसे आयोजन कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि और कार्य-प्रयोग को बढ़ावा देते हैं। संस्थान के निदेशक डॉ. पी. के. राय ने कहा कि हिंदी केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, बल्कि जनसामान्य से संस्थानों को जोड़ने का सशक्त माध्यम है।

एसईसीएल का स्वच्छता अभियान वसंत विहार कॉलोनी में चला

बिलासपुर। स्वच्छता ही सेवा एवं स्पेशल कैंपेन 6 के अंतर्गत एसईसीएल द्वारा एक दिन, एक घंटा, एक साथ गतिविधि के तहत बिलासपुर स्थित वसंत विहार कॉलोनी के शिव मंदिर परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में एसईसीएल परिवार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सामूहिक श्रमदान के माध्यम से शिव मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र की साफ-सफाई की गई तथा कचरे एवं अन्य अपशिष्ट को एकत्र कर उचित तरीके से निस्तारित किया गया। अभियान के दौरान सभी ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने का संकल्प लिया। एक घंटे की इस सामूहिक पहल के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी और सामुदायिक सहभागिता की भावना को मजबूत किया गया। एसईसीएल की यह पहल स्वच्छता ही सेवा अभियान एवं स्पेशल कैंपेन 6 के उद्देश्यों को जनभागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाने तथा स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ परिवेश के निर्माण की दिशा में एक सार्थक कदम है।

भाजपा नेता ने मां का ट्रांसफर रुकवाने डेढ़ लाख रुपये देने का लगाया आरोप

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के कथित ट्रांसफर उद्योग की पोल अब भाजपा के अपने नेता ही खोल रहे हैं। नरहपुर जनपद पंचायत सदस्य भोपेश नेताम ने अपनी शिक्षिका मां का ट्रांसफर रुकवाने के लिए डेढ़ लाख रुपये देने का गंभीर आरोप लगाया है। नेताम का दावा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव फोन के बाद भी उन्हें पैसा देना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि भाजपा का अपना जनपद सदस्य अपनी मां का ट्रांसफर रुकवाने के लिए कथित रूप से पैसे देने की बात कह रहा है। भाजपा सरकार को बताना चाहिए कि आखिर वह कौन-सा तंत्र है जहां फोन से भी काम नहीं होता और बिना पैसे के काम अटक जाता है? प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भोपेश नेताम ने भाजपा संगठन मंत्री पवन साय और रामू रोहरा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। गंगरेल बांध के टैंजर को कथित रूप से फोन कर निरस्त करवाने, जनपद पंचायत अध्यक्ष पद की दवादेदारी को पैसे के दम पर खत्म करने और कथित लेनदेन के जरिए अध्यक्ष बनाने जैसे आरोप बेहद गंभीर हैं। ये आरोप किसी विश्वेश नेता ने नहीं, भाजपा के अपने नेता ने लगाए हैं।

नैटकॉन के लिए कोलकाता रवाना हुई क्रेडाई छत्तीसगढ़ की टीम

रायपुर। रायपुर में स्टेटकॉन 2026 के बेहद सफल आयोजन के बाद, क्रेडाई छत्तीसगढ़ की टीम क्रेडाई के 24वें नेशनल कॉन्फ्रेंस नैटकॉन 2026में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता रवाना हो गई है। यह तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 2, 3 और 4 अक्टूबर 2026 को कोलकाता के आईटीसी रॉयल बंगाल में हो रहा है। इस साल नैटकॉन की थीम द इंडियन रियल एस्टेट डायलॉग रखी गई है। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सहित देश भर के कई बड़े पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट्स रियल एस्टेट के भविष्य पर चर्चा करेंगे इस अहम राष्ट्रीय सम्मेलन में क्रेडाई छत्तीसगढ़ की प्रतिनिधित्व एक खास प्रतिनिधिमंडल कर रहा है। इस टीम में क्रेडाई नेशनल के ईसी मेंबर आनंद सिंघानिया, क्रेडाई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पंकज लाहोटी, चेयरमैन मृणाल गोलछा, सचिव अभिषेक बच्छावत एवम सदस्य विजय नथानी , राकेश पांडेय, रवि फतनानी, अशोक खूबचंदानी, संजय बघेल, प्रीतेश कटारिया, रमेश राव , संजय रहेजा , विजय अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, अशोक मूंदड़ा , अक्षय पांडे , संजना बघेल और सत्येंद्र अग्रवाल भी इस प्रतिनिधिमंडल का अहम हिस्सा हैं।

सरकार नशे के कारोबार को रोक नहीं पदयात्रा निकाल रहे : कांग्रेस

रायपुर। भाजपा के द्वारा चलाया जा रहे नशा मुक्ति अभियान पर प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार नशे के कारोबार को रोक नहीं पा रही और भाजपाई नशा मुक्ति अभियान की नीटेंको कर रहे है। युवा और नाबालिक बुरी तरह से सुखे नशे के चपेट में आ चुके हैं। राजधानी सहित बड़े शहरों के आउटर संचालित कैफे, फार्महाउस और बार में अवैध नशे का जमकर कारोबार हो रहा है। गांजा, अफीम, चरस, कोकीन, हेरोइन, एमडीएमए, स्मैक, ब्राउन शुगर से लेकर कफ सिरप, नाइट्रोटेन, अल्ट्राजोलम, चंदागोली खुलेआम बिक रहा है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि नशे के बढ़ते कारोबार के कारण ही प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। लूटमार, हत्या, चोरी, डकैती और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पिछले दो सालों में कई गुना बढ़ा है, जिसका असल कारण नशाखोरी ही है। गुजरात का मुद्रा पोर्ट दुनिया भर में अवैध ड्रग्स के कारोबार का मुख्य केंद्र बना हुआ है, हजारों करोड़ के ड्रग्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान होकर मुद्रापोर्ट के रास्ते पूरे देश में फैल रहे हैं। एक साल पहले राजधानी रायपुर के गंज थाने में विशाल कुमर नाम के एक फज्जी आईबी अधिकारी को गिरफ्तारी हुई थी।

उप मुख्यमंत्री साव ने बहतराई खेल अकादमी के अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों का किया सम्मान

देश का पहला हॉकी लीग छत्तीसगढ़ में होगा : साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार अभिनव पहल कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में 21 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक पुरुष हॉकी लीग का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा, जो इस तरह की हॉकी लीग का आयोजन करने जा रहा है। लीग की टैगलाइन 'चलव रे संगी हॉकी खेलबो' रखी गई है। इसमें छह टीमों में हिस्सा लेंगी, जिनका नामकरण छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पहचान के अनुरूप किया गया है।

श्री साव ने बिलासपुर के बहतराई स्थित खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में ये बातें कहीं। उन्होंने एशियन



गेम्स-2026 में कबड्डी की स्वर्ण पदक विजेता सुश्री संजू देवी तथा जूनियर हॉकी एशिया कप-2026 की स्वर्ण पदक विजेता सुश्री मधु सिदार और सुश्री गीता यादव को सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने की।

समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा सुश्री संजू देवी के लिए पूर्व में घोषित 51 लाख रुपए की सम्मान राशि का चेक प्रदान किया गया। वहीं मधु सिदार और गीता यादव को 11 लाख 12 हजार रुपए प्रत्येक को विशेष सहायता पैकेज देने की घोषणा की गई।

कार्यक्रम में दोनों को इसमें से तत्काल 2-2 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। श्री साव ने तीनों खिलाड़ियों को शाल और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों में परिवार के योगदान का सम्मान करते हुए उप मुख्यमंत्री ने तीनों खिलाड़ियों के परिजनों को भी शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र के प्रशासनिक भवन में नवनिर्मित ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि यह बिलासपुर और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए उत्साह, उत्साह और गौरव का दिन है। इन खिलाड़ियों ने इसी सेंटर में खेलना सीखा, अपनी प्रतिभा को निखारा और कठिन परिश्रम के बल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया।

मंत्री दयालदास बघेल ने किया पौधरोपण दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा, संकल्प और कृतित्व की भावना को आत्मसात करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल ने आज बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम संबलपुर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन पर्यावरण के संवर्धन के बिना संभव नहीं है, इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दे।

ग्राम संबलपुर में आयोजित भव्य पौधरोपण कार्यक्रम में हजारों पौधे रोपे गए। मंत्री श्री बघेल ने स्वयं अपने हाथों से पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। इसके



बाद जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्कूली छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों ने भी उत्साह के साथ पौधरोपण किया। पूरा परिसर 'पेड़ लगाओ-जीवन बचाओ' के नारों से गुंज उठा। कार्यक्रम में कटहल, नीम, पीपल, बरगद, आम, जामुन और गुलमोहर सहित फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्री बघेल ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए आव्हान किया। उन्होंने कहा कि एक पेड़ लगाना सौ पुण्यों के बराबर है।